शंघाई भावना का नवीनीकरण

शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता

भारतीय वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस, नई दिल्ली
2022

© आईसीडब्ल्यूए 2022

अस्वीकरण: इन लेखों में विचार, विश्लेषण और सिफारिशें लेखकों के हैं।

विषय-सामग्री

आमुख......5

भारत और शंघाई सहयोग संगठन: 2023 शिखर सम्मेलन के लिए उत्सुक
डी. बी. वेंकटेश वर्मा......7

शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारतीय जुड़ाव: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य
के वारिकू......15

भारत, मध्य एशिया और एससीओ:संभावनाएं और चुनौतियां
एस. के. पांडे......33

लेखकों के बारे में 45

शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना था। यह एससीओ कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से और बड़े पैमाने पर भाग ले रहा है। भारत ने नवंबर 2020 में एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। महामारी के कारण, इसका आयोजन यह वर्चुअल रूप में किया गया था। भारत 2022-23 की अवधि के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभालने वाला है। संगठन के विस्तार और एससीओ क्षेत्र और उसके पड़ोस में कुछ महत्वपूर्ण विकास को देखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण अध्यक्षीय कार्यकाल होने के लिए तैयार है।

एससीओ की भारत की अध्यक्षता का समारोह मानाने और यूरेशियन संगठन के साथ अपने जुड़ाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, आईसीडब्ल्यूए ने कूटनीति और शिक्षाविदों के प्रशंसित भारतीय विशेषज्ञों द्वारा इस विषय पर शोध-पत्र तैयार किए हैं। रूसी संघ में भारत के पूर्व राजदूत, राजदूत डी बी वेंकटेश वर्मा ने एससीओ के विकास पर अपना दृष्टिकोण राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों से आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक मुद्दों के व्यापक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाली अपनी प्रारंभिक प्राथमिकताओं पर दिया है। उन्होंने रेखांकित किया कि सदस्यों को एससीओ के संस्थापक दस्तावेजों और 'शंघाई भावना' की भावना के अनुरूप होने की आवश्यकता है। प्रोफेसर के. वारिकू अपने विश्लेषण में एससीओ और इसकी गतिविधियों का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वह इसे एक गैर-पश्चिमी संगठन कहते हैं जो सदस्यों के बीच अभिसरण की एक विशाल संभावना प्रदान करता है। वह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें भी करता है। प्रोफेसर संजय के. पांडे एससीओ के उद्भव के पीछे क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति पर चर्चा करते हैं। वह संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए एससीओ के संबंध में भारत के उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं।

विशिष्ट लेखकों ने संगठन के पहलुओं और यूरेशिया और उससे आगे के साथ जुड़ाव की भारत की धारणाओं और आकांक्षाओं को कवर करने वाले तीन अलग-अलग लेखों में अपने समृद्ध ज्ञान और अनुभव को साझा किया है। आईसीडब्ल्यूए को आशा है कि ये शोध-पत्र इस विषय पर ज्ञान का विस्तार करने के उद्देश्य को पूरा करेंगे और एससीओ के बारे में सूचित परिचर्चा में योगदान देंगे, विशेष रूप से संगठन की भारत की अध्यक्षता की अवधि में।

विजय ठाकुर सिंह

महानिदेशक

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस

सितंबर 2022

भारत और शंघाई सहयोग संगठन
2023 शिखर सम्मेलन की ओर उन्मुख

डी. बी. वेंकटेश वर्मा

2023 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 23 वें शिखर सम्मेलन के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नेताओं की मेजबानी करेंगे। चूंकि भारत 2017 में रूस में उफा शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में चीन में क़िंगदाओ शिखर सम्मेलन और 2019 में बिश्केक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। रूस द्वारा आयोजित 2020 शिखर सम्मेलन कोविड महामारी के कारण वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। एससीओ की शासनाध्यक्ष परिषद (एचओजी) की बैठक की अध्यक्षता 30 नवंबर 2020 को हमारे उपराष्ट्रपति ने की थी। एससीओ के 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी उज्बेकिस्तान समरकंद में करेगा। 2023 में, भारत पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह वर्ष के दौरान जी 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते कद का प्रतीक है।

एससीओ अब दो दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में है। इसकी उत्पत्ति रूस और चीन दोनों की साझा इच्छा में निहित है कि वे सीमा मुद्दों की परस्पर चिंताओं पर एक संवाद मंच बनाने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन स्थापित करें और एक-दूसरे को आश्वस्त करें कि न तो मध्य एशिया में उनकी सामान्य परिधि में एकतरफा हितलाभ की तलाश होगी। यूरेशियन भूभाग पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रभाव के विस्तार के लिए जगह को कम करने में भी उनकी आम रुचि थी। मध्य एशिया के युवा और नवोदित राष्ट्रों-शुरू में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और बाद में उजबेकिस्तान में शामिल होने से एससीओ में योग्यता दो बड़े सदस्यों से विभिन्न क्षेत्रों में हितलाभ प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में देखी गई, लेकिन मध्य एशियाई क्षेत्र में उनके बीच प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संगठन का उपयोग भी किया।

अफगानिस्तान के घटनाक्रम, व्यापक क्षेत्र में आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खतरे के साथ-साथ अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अतिरिक्त क्षेत्रीय सैन्य बलों की उपस्थिति का एससीओ पर प्रभाव पड़ा। हालांकि अन्य क्षेत्रीय देशों-भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया और ईरान के बीच 2004-2005 की शुरुआत में एससीओ में पर्यवेक्षक बनने की रुचि थी, लेकिन 2016 के उफा शिखर सम्मेलन तक भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय नहीं लिया गया था। एससीओ की भारत की अध्यक्षता के दौरान ईरान द्वारा 2023 में पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिकताएं पूरी करने की आशा है।

एससीओ में अन्य देशों में काफी रुचि है। बेलारूस जो 2010 से एक पर्यवेक्षक रहा है, उसकी अब पूर्ण सदस्यता में रुचि है। कतर, मिस्र, सऊदी अरब, श्रीलंका, तुर्की, कंबोडिया, अजरबैजान, नेपाल और आर्मेनिया, जिन्हें पहले से ही एससीओ के साथ यह दर्जा प्राप्त है, वार्ता भागीदारों के रूप में शामिल हो सकते हैं। एससीओ ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन), कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआईएस), एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान), कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (सीएसटीओ), आर्थिक सहयोग संगठन (ईसीओ), एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए) और अन्य सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहकारी संबंध स्थापित किए हैं। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है और इसका क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र ताशकंद में स्थित है।

2018 में, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी प्राथमिकताओं का संक्षिप्त नाम करण किया था–सुरक्षित-सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण। यह अनिवार्य रूप से 2023 शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक और अग्रगामी प्राथमिकताओं को दर्शाता है जो आने वाले वर्षों में एससीओ गतिविधियों को नई गति दे सकता है।

मध्य एशिया के युवा और नवोदित राज्यों-शुरू में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और बाद में उजबेकिस्तान में शामिल होने से एससीओ में योग्यता दो बड़े सदस्यों से विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में देखी गई, लेकिन मध्य एशियाई क्षेत्र में उनके बीच प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संगठन का उपयोग भी किया गया।

यह महत्वपूर्ण है कि एससीओ अपनी प्रारंभिक प्राथमिकताओं से पल्लिवत हुआ है जो राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक मुद्दों के व्यापक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जिनका राष्ट्रों के बीच संबंधों को विनियमित करने तक सीमित होने के बजाय लोगों पर प्रभाव से अधिक लेना-देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में, हमारी प्राथमिकताओं का संक्षिप्त नामकरण किया था-सुरक्षित-सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण संरक्षण। यह अनिवार्य रूप से 2023 शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक और अग्रगामी प्राथमिकताओं को दर्शाता है जो आने वाले वर्षों में एससीओ गतिविधियों को नई गति दे सकता है।

लद्दाख में चीन का मुखर व्यवहार और सीमा पर बड़ा सैन्य निर्माण एससीओ के संस्थापक दस्तावेजों की मूल भावना के अनुरूप नहीं है, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की आवश्यकता को रेखांकित करने के अलावा सैन्य बल के उपयोग के गैर-उपयोग या खतरे और पड़ोसी क्षेत्रों में एकतरफा सैन्य श्रेष्ठता के त्याग पर भी जोर देता है।

बढ़ती जटिल अंतरराष्ट्रीय स्थिति एक सफल एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित करने की चुनौतियों को बढ़ाएगी। लद्दाख में चीन का मुखर व्यवहार और सीमा पर बड़ा सैन्य निर्माण एससीओ के संस्थापक दस्तावेजों की मूल भावना के अनुरूप नहीं है, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की आवश्यकता को रेखांकित करने के अलावा सैन्य बल के उपयोग के गैर-उपयोग या खतरे और पड़ोसी क्षेत्रों में एकतरफा सैन्य श्रेष्ठता के त्याग पर भी जोर देता है1। यह 'शंघाई भावना' के पालन पर भी प्रश्न करता है, अर्थात् आपसी विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, संयुक्त परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान और सामूहिक विकास की आकांक्षा, कि चीनी कार्रवाई न केवल भारत के साथ बल्कि अन्य पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में विरोधाभासी प्रतीत होती है। सहयोग की अंतर्निहित क्षमता को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है यदि एससीओ के सदस्य राष्ट्रों को अपने आपसी संबंधों में विश्वास की कमी है। एससीओ में निर्णय लेने के लिए बहुमत के निर्णय लेने का सहारा लेने के बजाय आम सहमति के सिद्धांत पर टिके रहना चाहिए जो लंबी अवधि में समर्थन को खत्म कर देगा। एससीओ की सदस्यता बढ़ने के साथ यह और भी महत्वपूर्ण होगा।

एससीओ में निर्णय लेने के लिए बहुमत के निर्णय लेने का सहारा लेने के बजाय आम सहमति के सिद्धांत पर टिके रहना चाहिए जो लंबी अवधि में समर्थन को खत्म कर देगा। एससीओ की सदस्यता बढ़ने के साथ यह और भी महत्वपूर्ण होगा।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष एससीओ विचार-विमर्श पर प्रभाव डालेगा, जो सदस्य देशों के मन में राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा की चिंताओं पर विचार करेगा, न केवल एससीओ का बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी एक प्रमुख सिद्धांत है और साथ ही न केवल संघर्ष क्षेत्रों में बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और नाटो की सैन्य और आर्थिक प्रतिक्रिया के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भी होंगे। पश्चिम द्वारा लगाए गए रूस विरोधी उपाय एससीओ क्षेत्र की स्थिरता पर आघात करेंगे। अस्थिरता के प्रमुख कारक अफगानिस्तान और विभिन्न मध्य एशियाई राष्ट्रों में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। इनका सीधा असर एससीओ पर पड़ेगा। रूस के साथ-साथ बेलारूस भी एससीओ को अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों के कारण अन्यथा प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय स्थान के संदर्भ में राहत प्रदान करने के रूप में देख सकता है। रूस इतना बड़ा देश है कि उसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस दिशा में चल रहे प्रयासों का यूरेशिया के लिए महत्वपूर्ण अस्थिर प्रभाव होगा। एससीओ में हमारे दृष्टिकोण, विशेष रूप से राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक उपयोग या एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम के काम जैसे मुद्दों पर रूस के साथ हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी।

> पश्चिम द्वारा लगाए गए रूस विरोधी उपाय एससीओ क्षेत्र की स्थिरता पर आघात करेंगे। अस्थिरता के प्रमुख कारक अफगानिस्तान और विभिन्न मध्य एशियाई राज्यों में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। इनका सीधा असर एससीओ पर पड़ेगा।

एससीओ राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली आर्थिक मंदी चीन के लिए न केवल द्विपक्षीय रूप से बल्कि प्रस्तावित एससीओ विकास बैंक और एससीओ विकास कोष जैसे तंत्रों के माध्यम से एससीओ के माध्यम से अपने आर्थिक पदचिह्न का विस्तार करके शून्य को भरने के अवसर पैदा कर सकती है। इस चुनौती से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है-एससीओ गेट को पूरी तरह से बंद करने से मध्य एशियाई राष्ट्र निराश हो सकते हैं और चीन को एससीओ बहुपक्षीय तंत्र के प्रभाव को कम किए बिना प्रभाव के द्विपक्षीय चैनलों की तलाश करने की अनुमति मिल सकती है। बड़े पैमाने पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण, रूस मध्य एशिया में चीनी प्रभाव के विस्तार को कम करने के लिए सड़क के कुछ नियम निर्धारित करने के लिए एससीओ का उपयोग करना चाह सकता है। हालांकि, एससीओ ने अफगानिस्तान पर एक संपर्क समूह की स्थापना की थी, लेकिन अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान के कब्जे के कारण अफगान विकास पर इसका प्रभाव मामूली था। इसलिए, एससीओ को नई परिस्थितियों में अपने लिए एक भूमिका तैयार करने की आवश्यकता होगी, विशेषकर मध्य एशिया की सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए। एससीओ आरएटीएस केंद्र विशेष चिंता के सुरक्षा मुद्दों पर मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ सहकारी संपर्क स्थापित करने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करता है-आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी, संगठित अपराध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से अवैध हथियार हस्तांतरण।

> हालांकि एससीओ ने अफगानिस्तान पर एक संपर्क समूह की स्थापना की थी, लेकिन अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान के कब्जे के कारण अफगान विकास पर इसका प्रभाव मामूली था। इसलिए एससीओ को नई परिस्थितियों में अपने लिए एक भूमिका तैयार करने की आवश्यकता होगी, खासकर मध्य एशिया की सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए।

> हमारी रुचि भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहमति के अनुरूप कनेक्टिविटी के मुद्दों पर एससीओ में नियम और मानदंड स्थापित करने में है। यह एक कठिन कार्य लग सकता है लेकिन लंबी अवधि में आवश्यक है।

एससीओ में पाकिस्तान की भूमिका (जो द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने पर रोक लगाता है) या अपने बीआरआई

या सीपीईसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में पाक-चीन गठजोड़ के संबंध में भी उचित सतर्कता आवश्यक है, जो कश्मीर में भारत की संप्रभुता के मुद्दों पर अतिक्रमण करता है। साथ ही, भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहमत तर्ज पर कनेक्टिविटी के मुद्दों पर एससीओ में नियम और मानदंड स्थापित करने में हमारी रुचि है। ईरान के एससीओ में शामिल होने की संभावना न केवल भारत के लिए बल्कि मध्य एशियाई राष्ट्रों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) के आकर्षण में एक नया आयाम जोड़ेगी। एससीओ में महाद्वीपीय कनेक्टिविटी को समुद्री कनेक्टिविटी की सुरक्षा के साथ-साथ चलना होगा जो क्वाड में प्राथमिकता है। एससीओ को कनेक्टिविटी पर उन मानदंडों का समर्थन करना चाहिए जो पाकिस्तान को भारत को अफगानिस्तान के पूर्ण पारगमन अधिकारों की अनुमति देने के लिए मजबूर करेंगे।

> भारत ने एससीओ एजेंडा को उन क्षेत्रों में विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो अधिक लोगों पर केंद्रित हैं।

अपने अस्तित्व के पहले पंद्रह वर्षों की तुलना में, जो मुख्य रूप से राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित था, एससीओ ने पिछले सात वर्षों में अपने दूसरे चरण में एक व्यापक आर्थिक और विकासात्मक एजेंडा हासिल किया है। भारत ने एससीओ एजेंडा को उन क्षेत्रों में विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो अधिक लोगों पर केंद्रित हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी और कोविड महामारी ने आर्थिक एजेंडे में तात्कालिकता की एक और भावना जोड़ दी है। एससीओ ने महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं विकसित की हैं-2025 तक एससीओ विकास रणनीति के कार्यान्वयन के लिए और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए; 2030 तक एससीओ क्षेत्र के लिए एक आर्थिक विकास रणनीति के लिए एक पहल भी है। काफी संभावना वाले अन्य प्रस्ताव हैं-एक एससीओ आर्थिक मंच, अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के विकास के लिए कार्यक्रम के साथ-साथ एससीओ विकास बैंक और एससीओ विकास कोष के निर्माण के प्रस्ताव।

> एससीओ भारत के भू-राजनीतिक हितों के लिए उच्च महत्व का समूह है और भारत की ओर से इसी तरह उच्च ध्यान देने योग्य है। एससीओ से मुंह मोड़ने से यह क्षेत्र चीन के लिए खुला रह जाएगा। रूस, जिसने भारतीय सदस्यता को आगे बढ़ाया और मध्य एशियाई राज्य चाहते हैं कि भारत अधिक सक्रिय भूमिका निभाए।

सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में संयुक्त बुनियादी ढांचा विकास, औद्योगिक सहयोग, निवेश परियोजनाओं का डेटा बैंक, सीमा शुल्क सहयोग, डिजिटलीकरण और आईटीसी, प्रौद्योगिकी पार्कों के पूल, स्टार्ट अप और नवाचार, गरीबी में कमी, क्षेत्रीय परिवहन और कनेक्टिविटी परियोजनाएं, ऊर्जा सहयोग, खाद्य सुरक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, महामारी सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा और टेलीमेडिसिन, पर्यावरण संरक्षण,

संस्कृति, पर्यटन, सार्वजनिक कूटनीति, खेल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला और युवा मामले शामिल हैं।

> एससीओ के पास पहले से ही अंतर-राज्य व्यवहार को विनियमित करने के लिए सिद्धांतों और मानदंडों का एक ढांचा है जो यूरेशियन महाद्वीप पर स्थिरता और पूर्वानुमान के लिए आवश्यक हैं। यह सच है कि एससीओ के सदस्य देश इसके सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए और अधिक कर सकते हैं और इस प्रकार समूह को मजबूत कर सकते हैं।

हालांकि, एससीओ के अपने एजेंडे को व्यापक बनाने के प्रयास स्वागत योग्य विकास है, लेकिन उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। चीन एससीओ का उपयोग एससीओ क्षेत्र में बीआरआई, वैश्विक विकास और सुरक्षा पहल जैसे मुद्दों पर अपने राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करता रहा है, जिसमें एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ बहुत कम पूर्व परामर्श होता है। जबकि रूस हमेशा इस संबंध में चीन का समर्थन नहीं करता है, यह अक्सर जैव-सुरक्षा और बाहरी अंतरिक्ष जैसे राजनीतिक या सुरक्षा मुद्दों पर समर्थन के बदले में चीन का समर्थन करने के लिए मजबूर होता है, जिसमें एक सुदृढ़ अमेरिका विरोधी कोण है। अपर्याप्त परामर्श और क्रॉस-लिंकेज की कमी अक्सर एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां सदस्य राष्ट्रों के लिए मूल्य बनाने के लिए काफी क्षमता के प्रस्तावों को विश्वास और समझ की कमी के कारण असमान समर्थन मिलता है। एससीओ का उपयोग वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन वैश्विक मुद्दों पर मानक निर्माण के लिए नहीं, जो संबंधित अंतरराष्ट्रीय निकायों का विशेषाधिकार होना चाहिए जिनके पास ऐसे मामलों के लिए जनादेश है।

> एससीओ की बैठकें भारत को एससीओ के अन्य सदस्यों पर दबाव डालने का अवसर प्रदान करती हैं कि वे अपने कार्यों को एससीओ के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुरूप लाएं, विशेष रूप से जिसे 'शंघाई भावना' कहा जाता है।

दूसरा प्रमुख कारक पर्याप्त क्षमता और संसाधनों की कमी है, विशेष रूप से मध्य एशियाई राष्ट्रों के बीच सहयोग के सहमत क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए। एससीओ सचिवालय और आरएटीएस सेंटर के अलावा, एससीओ ने अभी तक कोई प्रमुख संस्थान विकसित नहीं किया है जो आर्थिक सहयोग के अपने एजेंडे को बढ़ावा दे सके। चूंकि एससीओ के सदस्य देश ब्रिक्स और जी 20 में अन्य क्षेत्रीय संगठनों-भारत, रूस और चीन में भी भाग लेते हैं, सीआईएस, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू), सीआईसीए आदि में कुछ मध्य

एशियाई राष्ट्र, एससीओ मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता या इच्छा तदनुसार प्रभावित होती

है। ग्रेटर यूरेशियन साझेदारी का उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय है-विशेषकर अगर यह एससीओ को ईएईयू, आसियान के साथ जोड़ने में सक्षम है और जब स्थितियां यूरोपीय संघ के साथ भी अनुमति देती हैं, इस प्रकार एक पैन-यूरेशियन सहकारी मंच का निर्माण होता है। हालांकि, एससीओ सदस्य देशों की अलग-अलग प्राथमिकताओं के कारण यह उद्देश्य बाधित होता है-जबकि चीन का अधिक आक्रामक एजेंडा है, मध्य एशियाई राष्ट्र और रूस अक्सर अपने हितों को अनुकूलित करने के लिए एससीओ एजेंडे का उपयोग करने के लिए विभाजित होते हैं।

एससीओ का उपयोग भारत द्वारा महाद्वीपीय और समुद्री आयामों पर अपने मूल हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए किया जा सकता है।

अपनी स्पष्ट सीमाओं के बावजूद, एससीओ भारत के भू-राजनीतिक हितों के लिए उच्च महत्व का समूह है और भारत की ओर से उच्च ध्यान देने योग्य है। एससीओ से मुंह मोड़ने से यह क्षेत्र चीन के लिए खुला रह जाएगा। रूस, जिसने भारतीय सदस्यता को आगे बढ़ाया और मध्य एशियाई राष्ट्र चाहते हैं कि भारत अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। यह कि इसमें मुख्य यूरेशियन महाद्वीप के सभी मुख्य नायक शामिल हैं और अन्य प्रासंगिक देशों से रुचि आकर्षित कर रहे हैं, एससीओ की निरंतर प्रासंगिकता का संकेत है।

एससीओ के पास पहले से ही अंतर-राष्ट्र व्यवहार को विनियमित करने के लिए सिद्धांतों और मानदंडों का एक ढांचा है जो यूरेशियन महाद्वीप पर स्थिरता और पूर्वानुमान के लिए आवश्यक हैं। यह सच है कि एससीओ के सदस्य देश इसके सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए और अधिक कर सकते हैं और इस प्रकार समूह को सुदृढ़ कर सकते हैं। यह समुद्री डोमेन के विपरीत है जहां मानदंड कम अच्छी तरह से विकसित या संहिताबद्ध हैं और यहां तक कि कम सम्मानित हैं। जब एससीओ के संस्थापक दस्तावेजों का मसौदा तैयार किया गया था, तब भारत भले ही इसका सदस्य नहीं रहा हो, लेकिन भारत ने पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के समय उनके पालन के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। एससीओ की बैठकें भारत को एससीओ के अन्य सदस्यों पर दबाव डालने का अवसर प्रदान करती हैं कि वे अपने कार्यों को एससीओ के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुरूप लाएं, विशेष रूप से जिसे 'शंघाई भावना' कहा जाता है।

2023 शिखर सम्मेलन की तैयारी स्टार्ट अप, अभिनव प्रौद्योगिकियों, डिजिटल वित्त, फार्मा और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हाल के वर्षों में प्रगति के संदर्भ में 'न्यू इंडिया' को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी।

भारत ने विभिन्न एससीओ शिखर सम्मेलनों और एचओएस और एचओजी स्तर पर उच्च स्तरीय बैठकों के साथ-साथ एससीओ विदेश मंत्रियों, एनएसए, रक्षा मंत्रियों, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, केंद्रीय बैंकों, संस्कृति और अन्य मंत्रालयों और विभागों में नियमित रूप से भाग लिया है। शुरुआती अंतराल के बाद, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और परामर्श की कठिनाइयों के बावजूद कार्य स्तर की बैठकों में भारत की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने हमारी एससीओ गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कदम उठाए हैं-जिसमें एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव के तहत एक अलग एससीओ डिवीजन बनाना शामिल है, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में भी अच्छा काम किया है। बीजिंग में एससीओ सचिवालय से मान्यता प्राप्त भारत का एक अलग एससीओ मिशन है और उसने ताशकंद में सचिवालय और आरएटीएस सचिवालय में दो-दो अधिकारियों को तैनात किया है। रूसी और चीनी एससीओ की केवल दो आधिकारिक भाषाएं हैं, जो एससीओ से संबंधित गतिविधियों पर एक अतिरिक्त चुनौती भी देती हैं।

2023 में एससीओ की भारत की अध्यक्षता समूह को नई दिशाओं में चलाने और इसकी गतिविधियों को गति देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है जो इसके सदस्यों, विशेष रूप से मध्य एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रों को लाभान्वित करेगी। जबकि एससीओ का यूरेशियन महाद्वीप पर एक सहकारी मंच के रूप में अपना महत्व है, आगामी शिखर सम्मेलन एससीओ एजेंडे के संदर्भ में हमारी महाद्वीपीय नीति को मुख्यधारा में लाने का एक अवसर है। यह हमारी एससीओ गतिविधियों को ब्रिक्स, आरआईसी, ईएईयू और जी20 के साथ हमारे जुड़ाव में हमारी गतिविधियों के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है ताकि ये सभी मंच, अपने व्यक्तिगत जनादेश रखते हुए समन्वित तरीके से हमारी प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करें।

आगामी शिखर सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं में राजनीतिक और सुरक्षा दोनों आयामों के साथ-साथ आर्थिक, व्यापार और सांस्कृतिक आयाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आयाम मौलिक स्तर पर एक-दूसरे से संबंधित हैं। एससीओ का उपयोग भारत द्वारा महाद्वीपीय और समुद्री आयामों पर अपने मूल हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए किया जा सकता है। चीनी मुखर मुद्राओं के संबंध में, एससीओ की उपयोगिता अंतर-राष्ट्र व्यवहार को कम करने के लिए है, विशेष रूप से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में। इसमें उन प्रस्तावों पर अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ परामर्श करना शामिल होगा जो इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। रूस और मध्य एशियाई दोनों देश भारत के ऐसे प्रयासों का स्वागत करेंगे। भारत आतंकवाद से निपटने और रक्षा अभ्यासों के संबंध में अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा सकता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों के लिए एक आरामदायक स्तर बनाना है।

एससीओ के आर्थिक और व्यापारिक एजेंडे में कोविड महामारी के बाद वैश्वीकरण में गंभीर व्यवधानों और यूक्रेन के साथ संघर्ष के संदर्भ में रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अन्योन्याश्रितता के हथियारीकरण को ध्यान में रखना होगा। मध्य एशियाई राष्ट्रों की नाजुक अर्थव्यवस्थाओं पर इन घटनाक्रमों के प्रभाव को कम

करने के तरीकों और साधनों को खोजना और बाजार हिस्सेदारी, शोषक निवेश या अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के मामले में पैठ बनाने के लिए चीन द्वारा वर्तमान संकट का एकतरफा लाभ उठाने की संभावना को रोकना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक उपयोग की संभावनाओं और व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए अभिनव तंत्र को सक्रिय तरीके से खोजा जाना चाहिए। आईएनएसटीसी के पूर्ण संचालन से चीन द्वारा दिए जा रहे वैकल्पिक बीआरआई लिंकेज की तुलना में एससीओ कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। एससीओ को हमारे हितों के अनुरूप दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमारी ओर से पुनर्विचार आवश्यक हो सकता है। एससीओ गतिविधियों के इन आयामों की उपेक्षा यूरेशियन महाद्वीप पर हमारे हाशिए के भविष्य के जोखिम पैदा करेगी।

2023 शिखर सम्मेलन की तैयारी स्टार्ट अप, अभिनव प्रौद्योगिकियों, डिजिटल वित्त, फार्मा और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हाल के वर्षों में प्रगति के संदर्भ में 'न्यू इंडिया' को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी। शिखर सम्मेलन स्तर पर स्टार्ट अप, युवा वैज्ञानिक सम्मेलनों, पारंपरिक चिकित्सा और युवा शैक्षणिक सम्मेलनों पर पहल का समर्थन किया जा सकता है। बौद्ध संबंध, पर्यटन और शैक्षिक संबंधों सहित सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को उजागर करने से एससीओ में लोगों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग बढ़ सकता है। पश्चिमी अवधारणाओं के विपरीत, पारंपरिक चिकित्सा और पारंपरिक खेलों के एससीओ प्लेटफार्मों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार समूह के लिए एक नई प्रोफ़ाइल दे सकता है।

भारत में एक मुख्य सहकारी गतिविधि के संबंध में कम से कम एक एससीओ केंद्र स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है जैसा कि एससीओ के अन्य सदस्य देश पहले ही कर चुके हैं। अकादमिक और थिंक टैंक स्तर पर, एससीओ मामलों के बारे में रुचि और विशेषज्ञता को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है जो अन्य एससीओ सदस्यों के साथ थिंक-टैंक बातचीत के लिए आवश्यक होगा। आईसीडब्ल्यूए में एससीओ अध्ययन केंद्र की स्थापना के साथ एक शुरुआत की गई है। यूरेशियन मुद्दों पर विशेषज्ञता विकसित करना हमारे नीतिगत उद्देश्यों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक होगा।

एससीओ का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि भारत अपनी मुख्य गतिविधियों पर कितना काम करने के लिए तैयार है जो रूस और मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करेगा और चीन पर नजर रखने के लिए उसे पूरी सदस्यता के सामान्य हितों के विपरीत अपने हितों की छवि में एससीओ का दुरुपयोग करने से रोकेगा। यह हमारी कूटनीति की परीक्षा होगी लेकिन भारत ने बार-बार दिखाया है कि वह उड़ान भरने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 2023 का एससीओ शिखर सम्मेलन एक बार फिर इस बात को सिद्ध करेगा।

शंघाई सहयोग संगठन के मुद्दों और दृष्टिकोणों के साथ भारत का जुड़ाव

के वारिकू

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभरा है, जो रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य एशियाई गणराष्ट्रों के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया और बेलारूस को पर्यवेक्षकों और आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, तुर्की, मिस्र, कतर और सऊदी अरब को संवाद भागीदारों के रूप में जोड़ता है। एससीओ अपनी भौगोलिक कवरेज और आबादी के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है।

> एससीओ एक गैर-पश्चिमी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जो अपने सदस्यों के विचारों के व्यापक अभिसरण को दर्शाता है।

एससीओ एक गैर-पश्चिमी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जो अपने सदस्यों के विचारों के व्यापक अभिसरण को दर्शाता है। कट्टरपंथ, आतंकवाद और अलगाववाद के खतरे एससीओ सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करते हैं। आईएसआईएस का उदय और क्षेत्र में जड़ें जमाने के उसके निरंतर प्रयास इन सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाते हैं।

> सितंबर 2022 में एससीओ की अध्यक्षता में भारत की नियुक्ति भारत, रूस, चीन और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और पारस्परिक सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने, धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाने के अवसर प्रदान करती है।

अपनी सभी शिखर बैठकों के माध्यम से, एससीओ धार्मिक अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद के खतरों से लड़ने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। एससीओ को मध्य एशियाई गणराष्ट्रों की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देने और समेकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में देखा जाता है और इन देशों को किसी भी अतिरिक्त क्षेत्रीय हस्तक्षेप और दबाव से बचाने के लिए भी देखा जाता है। एससीओ के सदस्य देश सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक अतिवाद, अलगाववाद, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनसे शंघाई में अच्छे पड़ोसी, मित्रता और सहयोग की भावना से निपटा जा सकता है।

> एससीओ के सदस्य देश सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक अतिवाद, अलगाववाद, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनसे शंघाई में अच्छे पड़ोसी, मित्रता और सहयोग की भावना से निपटा जा सकता है।

सितंबर 2022 में एससीओ की अध्यक्षता में भारत की नियुक्ति भारत, रूस, चीन और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और पारस्परिक सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने, धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाने के अवसर प्रदान करती है। इससे न केवल इस क्षेत्रीय संगठन की प्रभावकारिता बढ़ेगी, बल्कि बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को भी बल मिलेगा। जब भारत ने 30 नवंबर 2020 को 19वें एससीओ शासनाध्यक्षों की आभासी बैठक की मेजबानी की, तो इसने आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में अपनी भूमिका बढ़ाने के अलावा एससीओ के सदस्य देशों के बीच सुदृढ़ सामाजिक-आर्थिक संबंध बनाने की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त की। एससीओ देशों की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से, भारत ने अगस्त 2020 में हाल ही में स्थापित एससीओ कंसोर्टियम ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सेंटर की पहली बैठक आयोजित की। व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, वित्त, शिक्षा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और पारंपरिक चिकित्सा, फार्मास्यूटिकल्स, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए पर्याप्त संभावना है। रूस और ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए समान विचारधारा वाले एससीओ देश भुगतान आदि के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की भी तलाश कर सकते हैं।

> यह प्राचीन काल से चली आ रही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की चेतना है और इस क्षेत्र के लोगों के मानस को प्रभावित करती है, जो सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक सहयोग के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान करती है।

सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना

भारत मध्य एशिया को अपने विस्तारित पड़ोसी और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखता है। मध्य एशियाई गणराष्ट्रों और भारत के बीच मौलिक मुद्दों पर विचारों और हितों का अभिसरण है जैसे; (क) अंतर-जातीय सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देकर सामाजिक सद्भाव और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता; (ख) धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता और धार्मिक कट्टरवाद का विरोध; (ग) सीमा पार आतंकवाद, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, धामक अतिवाद और जातीय-धामक अलगाववाद से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरे की पहचान; और (घ) राष्ट्र राष्ट्रों की क्षेत्रीय

अखंडता और राष्ट्र की सीमाओं की अनुल्लंघनीयता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता।

यदि हुइएन सियांग और फाहियान ने ऊंचे पामीर और काराकोरम पर्वतों को पार करके भारत की यात्रा की, तो कुमारजीव और बोद्धीधर्म भारत से चीन चले गए। इस ऐतिहासिक-सांस्कृतिक इंटरफेस ने भारतीय विचार और संस्कृति के संचरण के साथ-साथ खगोल विज्ञान, चिकित्सा, योग आदि में भारतीय अनुभवों को भी बढ़ावा दिया।

इस पारस्परिक राजनीतिक समझ को क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच विचार और कार्रवाई के तालमेल के माध्यम से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि भारत और मध्य एशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ हो सकें और जमीनी स्तर पर सद्भावना, प्रेम और सद्भाव के कोष में विकसित हो सकें।

भारतीय और मध्य एशियाई/यूरेशियन शिक्षा केन्द्रों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों आदि के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया। इसे सुव्यवस्थित और संस्थागत बनाने की आवश्यकता है, ताकि मध्य एशिया/यूरेशिया के भारतीय विशेषज्ञ अध्ययन/विशेषज्ञता के अपने क्षेत्रों में अपने समकक्षों के साथ सहयोग करने में सक्षम हो सकें।

व्यापार, विचारों और पारस्परिक सांस्कृतिक प्रभावों के आंदोलन ने इस क्षेत्र के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं पर गहरी छाप छोड़ी है। भारतीय मसालों, चाय, औषधीय जड़ी बूटियों आदि का लोकप्रिय उपयोग और मध्य एशिया, अफगानिस्तान और एससीओ के सदस्य देशों में आज भी भारतीय फिल्मों और गीतों की तलाश सदियों पुराने भारतीय संबंध को दर्शाती है। खगोल विज्ञान, दर्शन, भाषा, साहित्य, लोकगीत, वास्तुकला, कला और शिल्प, सुलेख, वस्त्र और भोजन की आदतों जैसे अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को अपनाने वाला सामान्य सांस्कृतिक पैटर्न भारत और इसके विस्तारित पड़ोस के बीच सामाजिक-आर्थिक संपर्क की प्रक्रिया में विकसित हुआ। यह प्राचीन काल से चली आ रही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की चेतना है और इस क्षेत्र के लोगों के मानस को प्रभावित करती है, जो सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक सहयोग के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान करती है। पारंपरिक नौरोज़ एशिया के प्रमुख हिस्सों-ईरान, उत्तरी अफगानिस्तान, अज़रबैजान, मध्य एशियाई गणराष्ट्रों और भारत के कुछ हिस्सों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह इस विशाल क्षेत्र के लोगों को उनके साझा इतिहास और विरासत की याद दिलाता है। इस तरह के सामान्य त्योहारों को मनाने की इस परंपरा को एससीओ ढांचे के माध्यम से भी लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

इसी तरह, भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिन्हें अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। जबकि सिल्क रूट ने हिमालय में पुरुषों, विचारों और वस्तुओं के ओवरलैंड आंदोलन की सुविधा प्रदान की, समुद्री मार्ग का उपयोग व्यापार और यात्रा उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। भारत के बौद्ध मिशनरियों ने चीन में बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो बौद्ध धर्मग्रंथों का भंडार बन गया। चीनियों के लिए, भारत ज्ञान की भूमि थी। यदि हुइएन सियांग और फाहियान ने ऊंचे पामीर और काराकोरम पर्वतों को पार करके भारत की यात्रा की, तो कुमारजीव और बोद्धीधर्म भारत से चीन चले गए। इस ऐतिहासिक-सांस्कृतिक इंटरफेस ने भारतीय विचार और संस्कृति के संचरण के साथ-साथ खगोल विज्ञान, चिकित्सा, योग आदि में भारतीय अनुभवों को भी बढ़ावा दिया। इतिहास के माध्यम से चीन-भारत संपर्कों की समृद्धि को देखते हुए, दोनों देशों के लिए पुराने संदेह और अवरोधों को दूर करते हुए आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक डोमेन में सहयोग करना और भी आवश्यक हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (29 नवंबर 2020-28 फरवरी 2021) में आयोजित साझा बौद्ध विरासत की एससीओ डिजिटल प्रदर्शनी ने क्षेत्र के लोगों के बीच साझा मूल्यों और संबंधों को उजागर करने में मदद की।

भारत पहले ही क्षेत्रीय भाषाओं में 10 भारतीय साहित्यिक क्लासिक्स का रूसी और चीनी की एससीओ भाषाओं में अनुवाद कर चुका है, जिन्हें औपचारिक रूप से 29 जून 2021 को एससीओ महासचिव को प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय और मध्य एशियाई/यूरेशियन शिक्षा केन्द्रों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों आदि के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया। इसे सुव्यवस्थित और संस्थागत बनाने की आवश्यकता है, ताकि मध्य एशिया/यूरेशिया के भारतीय विशेषज्ञ अध्ययन/विशेषज्ञता के अपने क्षेत्रों में अपने समकक्षों के साथ सहयोग करने में सक्षम हो सकें। यह मध्य एशिया/यूरेशिया पर विभिन्न अध्ययन केंद्रों/थिंक टैंकों को उदार समर्थन के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। सांस्कृतिक सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों का संयुक्त उत्पादन, पुस्तकों का प्रकाशन, प्रिंट और दृश्य सामग्री का आदान-प्रदान और कलाकारों का नियमित आदान-प्रदान है। भारत पहले ही क्षेत्रीय भाषाओं में 10 भारतीय साहित्यिक क्लासिक्स का रूसी और चीनी की एससीओ भाषाओं में अनुवाद कर चुका है, जिन्हें औपचारिक रूप से 29 जून 2021 को एससीओ महासचिव को प्रस्तुत किया गया था।

यह सही समय है कि सभी पुरावशेष, भितिचित्र, पांडुलिपियां, शिलालेख, कलाकृतियां आदि जो अफगानिस्तान, मध्य एशिया और शिनजियांग के विभिन्न हिस्सों में या तो स्थलों पर या स्थानीय संग्रहालयों में बिखरे हुए हैं, प्रलेखित हैं।

हम मूर्त विरासत के खजाने की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देंगे, जो भारत और क्षेत्र के बीच गहरे और ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधों का आधार है, ताकि नई और युवा पीढ़ी इस समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को अपनी स्मृति में आत्मसात कर सके। इस तरह की समृद्ध ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत की पहचान, स्थान, प्रलेखन और प्रसार का कार्य प्राथमिकता लेता है। यूनेस्को, जिसने अपनी प्रसिद्ध सिल्क रोड्स प्रोजेक्ट के अलावा मध्य एशिया में विभिन्न विरासत स्थलों की बहाली और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मध्य एशिया, चीन और भारत में पुरातत्व और इतिहास के संबंधित संस्थान संयुक्त रूप से इस कार्य को कर सकते हैं। प्राचीन वस्तुओं और पुरातात्विक स्थलों के वास्तविक प्रलेखन की दिशा में ठोस कदम अतीत को फिर से खोजने और स्वदेशी जातीय-सांस्कृतिक विरासत के आधार पर राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करने के लिए स्वतंत्र मध्य एशियाई गणराष्ट्रों की नीति के भीतर अनुकूल हैं।

यह सही समय है कि सभी पुरावशेष, भित्तिचित्र, पांडुलिपियां, शिलालेख, कलाकृतियां आदि जो अफगानिस्तान, मध्य एशिया और शिनजियांग के विभिन्न हिस्सों में या तो स्थलों पर या स्थानीय संग्रहालयों में बिखरे हुए हैं, प्रलेखित हैं। आईजीएनसीए और भारतीय विशेषज्ञों/पुरातत्वविदों को तत्काल काम करने की आवश्यकता है, साहित्यिक, ऐतिहासिक और कलात्मक कार्यों की पहचान और संरक्षण के लिए भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चीनी, खरोष्ठी, तुर्किक, फारसी, उइगर, मंगोलियाई, आदि में पुराने क्लासिक्स जो मध्य एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, उन्हें माइक्रोफिल्म किया जा सकता है और संभवतः अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया जा सकता है। भारत और एससीओ इन पुरावशेषों की पहचान, प्रलेखन, वीडियो फिल्मांकन और संरक्षण का एक व्यापक और ठोस कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं, जो अन्यथा गुमनामी में खो सकते हैं।

इसलिए, इस क्षेत्र में प्राचीन स्थलों को सांस्कृतिक पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में संरक्षित, संरक्षित, पुनर्स्थापित और विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भारत और एससीओ एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित करके पहल कर सकते हैं जिसमें पुरातत्व संस्थानों, राष्ट्रीय संग्रहालयों और एससीओ सदस्य देशों के सांस्कृतिक इतिहासकारों जैसी विशेष एजेंसियों को शामिल किया गया है। क्षेत्र के विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को शामिल करते हुए एक विशेष एससीओ सांस्कृतिक केंद्र वर्तमान में खंडहर में पड़े ऐसे प्राचीन स्थलों की खुदाई, संरक्षण और पुनर्स्थापन का कार्य कर सकता है, ताकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इंटरफेस की यह समृद्ध गवाही प्रकृति, समय और उपेक्षा की अनिश्चितताओं के माध्यम से नष्ट न हो। इन स्थलों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है जो बदले में पर्यटन और यातायात को बढ़ावा देगा।

क्षेत्र के विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को शामिल करते हुए एक विशेष एससीओ सांस्कृतिक केंद्र वर्तमान में खंडहर में पड़े ऐसे प्राचीन स्थलों की खुदाई, संरक्षण और पुनर्स्थापन का कार्य कर सकता है, ताकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इंटरफेस की यह समृद्ध गवाही प्रकृति, समय और उपेक्षा की अनिश्चितताओं के माध्यम से नष्ट न हो।

आतंकवाद की घटना ने कई और खतरनाक आयाम हासिल कर लिए हैं, विशेष रूप से धार्मिक आतंकवादी समूहों की बढ़ती भूमिका, छोटे हथियारों का प्रसार, नार्को-आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे राज्य के खिलाफ भाड़े के सैनिकों और आतंकवादियों का उपयोग करके एक राज्य द्वारा छद्म युद्ध।

आतंकवाद से निपटना

आतंकवाद का संकट जो मानवाधिकारों के विनाश में प्रकट हुआ है; अल्पसंख्यकों का जातीय-धार्मिक सफाया; बंधक बनाना; लक्षित हत्याएं; खदानें और बम विस्फोट; राज्यों में वैध नागरिक और राजनीतिक अधिकार को नष्ट करना; लोकतांत्रिक और बहुलवादी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करना; सार्वभौमिक रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मुख्य चुनौती के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों ने समय-समय पर आतंकवाद के सभी कृत्यों, तरीकों और प्रथाओं की स्पष्ट निंदा को दोहराया है, चाहे उनकी प्रेरणा की परवाह किए बिना, उनके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में, चाहे जो भी और जिसने भी किया हो, मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए कृत्यों के रूप में, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। वैध रूप से गठित सरकारों को अस्थिर करना, बहुलवादी समाज और कानून के शासन को कमजोर करना, जिसके राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रतिकूल परिणाम हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक अतिवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के घातक संयोजन का उद्भव नागरिकों के मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। अब समय आ गया है कि इस खतरे का डटकर मुकाबला किया जाए।

आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्यों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बार-बार निंदा और अपील के बावजूद, उनके अत्याचारों ने *फिदायीन* (आत्मघाती) और कार बम हमलों, अपहरण, महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष पीड़ितों का सिर कलम करने की और भी हिंसक और बर्बर अभिव्यक्तियाँ ग्रहण कर ली हैं। आतंकवाद की घटना ने कई और खतरनाक आयाम हासिल कर लिए हैं, विशेष रूप से धार्मिक आतंकवादी समूहों की बढ़ती भूमिका, छोटे हथियारों का प्रसार, नार्को-आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे राष्ट्र के खिलाफ भाड़े के सैनिकों और आतंकवादियों का उपयोग करके एक राष्ट्र द्वारा छद्म युद्ध। लोकतंत्र, नागरिक समाज और कानून के शासन के लिए आतंकवाद से उत्पन्न गंभीर खतरे का उचित संज्ञान लेते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 19 अक्तूबर 1999 को एक प्रस्ताव 1269 अपनाया, जिसमें "सभी राष्ट्रों से आतंकवादी कृत्यों को रोकने और दबाने, आतंकवादी हमलों के खिलाफ अपने नागरिकों और अन्य व्यक्तियों की रक्षा करने और प्रति व्यक्ति को न्याय के दायरे में लाने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया गया। 1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जिसमें आतंकवादी कृत्यों के अपराधियों को प्रत्यर्पित करने या मुकदमा चलाने का सिद्धांत शामिल था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपायों पर एक तदर्थ समिति की स्थापना की गई। नवंबर 1996 में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी)[1] का 'पहला मसौदा' वितरित किया, जो आतंकवाद की परिभाषा पर विचारों के मतभेद के कारण अभी भी गतिरोध में बंद है।

> आतंकवाद के आंतरिक और बाहरी दोनों विस्फोटक आयाम होते हैं। अपने बाहरी आयाम में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने और इससे प्रभावित राज्यों से भी मजबूत प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता है। अपने आंतरिक आयाम में, आतंकवाद अराजकता और अस्थिरता पैदा करता है, जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जिसमें आतंकवादी कृत्यों के अपराधियों को प्रत्यर्पित करने या मुकदमा चलाने के सिद्धांत के माध्यम से शामिल था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपायों पर एक तदर्थ समिति की स्थापना की गई। नवंबर 1996 में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) 1 का 'पहला मसौदा' प्रसारित किया, जो आतंकवाद की परिभाषा पर विचारों के मतभेद के कारण अभी भी गतिरोध में बंद है।

राज्यों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र निकायों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आतंकवाद के अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और अच्छी तरह से समन्वित अभियान शुरू करना आवश्यक हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक अतिवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के घातक संयोजन का उद्भव नागरिकों के मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। अब समय आ गया है कि इस खतरे का डटकर सामना किया जाए और इसका डटकर मुकाबला किया जाए। आतंकवाद की परिभाषा और व्याख्या पर शब्दार्थ अव्यवस्था, जैसा कि यह जातीय-धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ पवित्र युद्ध के नाम पर शुरू किए गए आतंकवादी अभियानों से संबंधित है, का कुछ राष्ट्रों द्वारा सीमा पार आतंकवाद के समर्थन में और अन्य राष्ट्रों के खिलाफ अपनी विदेश नीति रणनीति को आगे बढ़ाने में लीपापोती के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। परिणामतः, आतंकवाद की परिभाषा पर गतिरोध जारी है। इसलिए, ऐसी किसी भी मौजूदा खामियों को तुरंत दूर करना अनिवार्य हो जाता है जो आतंकवाद और इसके अपराधियों के खिलाफ दृढ़ और निवारक कार्रवाई की प्रक्रिया को बिना किसी अपवाद के राजनीतिक या अन्य विचारों के लिए बाधित करते हैं।

अपनी सभी शिखर बैठकों के माध्यम से, एससीओ धार्मिक अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद के खतरों से लड़ने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है।

आतंकवाद के आंतरिक और बाहरी दोनों विस्फोटक आयाम होते हैं। अपने बाहरी आयाम में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने और इससे प्रभावित राष्ट्रों से भी सुदृढ़ प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता है। अपने आंतरिक आयाम में, आतंकवाद अराजकता और अस्थिरता पैदा करता है, जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। चूंकि आतंकवाद का मुद्दा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा में केंद्र में आ गया है, इसलिए राष्ट्रों की ओर से आम सहमति पर पहुंचने के लिए तीन दृष्टिकोण प्रस्तावित हैं। पहला दृष्टिकोण एक कानूनी ढांचा तैयार करना और राष्ट्रों के भीतर आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए राष्ट्रों के भीतर तंत्र बनाना होना चाहिए। दूसरा, वैश्विक आतंकवाद से निपटने में अंतर-राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। इस संदर्भ में, एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से राष्ट्र सूचना साझा करने, अपने क्षेत्र के भीतर अपने नेटवर्क और समर्थन प्रणालियों के साथ अपराधियों की पहचान करके अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं। तीसरा दृष्टिकोण उन देशों की पहचान करना और उनकी निंदा करना है, जो अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद को प्रायोजित और बनाए रख रहे हैं।

राष्ट्रों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र निकायों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आतंकवाद के अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और अच्छी तरह से समन्वित अभियान शुरू करना आवश्यक हो जाता है। कट्टरपंथ, आतंकवाद और अलगाववाद के खतरे दुनिया भर में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करते हैं। अपनी सभी शिखर बैठकों के माध्यम से, एससीओ धार्मिक अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद के खतरों से लड़ने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। स्थापना के अपने प्रारंभिक वर्ष में, एससीओ सदस्य जून 2001 में शंघाई में मिले और 15 जून 2001 को *आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करने पर शंघाई कन्वेंशन* पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद, 2002 में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे पर समझौते का समापन हुआ। आरएटीएस की स्थापना आतंकवादी आंदोलनों के बारे में जानकारी एकत्र करने और आदान-प्रदान करने, आतंकवाद विरोधी नीतियों और कानूनों का मसौदा तैयार करने और उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने वाले सदस्य देशों के संबंधित संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए एक केंद्र के रूप में की गई थी। इन तीन बुराइयों का मुकाबला करने के लिए आरएटीएस तंत्र का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है। मार्च 2009 में मास्को में अफगानिस्तान पर आयोजित एससीओ के विशेष सम्मेलन ने "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को अपनाने के साथ-साथ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी कानूनी साधनों के विस्तार का आह्वान किया[2]।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जून 2018 में चीन के क़िंगदाओ शहर में आयोजित 18 वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में "आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुरी ताकतों" का मुकाबला करने के लिए सहयोग के 2019-2021 कार्यक्रम को सक्रिय रूप से लागू करने और 'शांति मिशन' और अन्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। 10 जून 2018 को संपन्न हुए 18वें एससीओ शिखर सम्मेलन में, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के मध्य एशियाई गणराष्ट्रों के सदस्य राष्ट्रों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए एक संयुक्त घोषणा को अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वय भूमिका के साथ एक एकीकृत वैश्विक आतंकवाद विरोधी मोर्चे के निर्माण का आह्वान किया। राजनीतिकरण या दोहरे मानदंडों के बिना। सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक संधि को अपनाने पर भी आम सहमति की मांग की, जो कुछ देशों द्वारा अपनाए गए दोहरे मानदंडों के कारण लंबित है। एससीओ के सदस्य देश इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादी विचारधारा के प्रसार और प्रसार का मुकाबला करने के अपने संकल्प में एकजुट थे, जिसमें सार्वजनिक रूप से आतंकवाद को उचित ठहराना भी शामिल था। एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ की "तीन बुरी ताकतों" का संयुक्त रूप से मुकाबला करने और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की विशेष भूमिका को मान्यता दी।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की भावना को ध्यान में रखते हुए, भारत निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एससीओ आम सहमति

दस्तावेज/मसौदा कन्वेंशन विकसित करके नेतृत्व कर सकता है:

- आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी उपाय इस तरह से किए जाने की आवश्यकता है ताकि मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो।

- सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र निकायों के बीच सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए, ताकि आतंकवादियों की गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण और अभियोजन सुनिश्चित किया जा सके।

- संयुक्त राष्ट्र निकायों और देशों को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं और मजबूरियों से प्रभावित हुए बिना, अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंक के कृत्यों के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए। आतंकवादी की परिभाषा की किसी भी अस्पष्टता या गलत व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र को पहचाने गए आतंकवादी संगठनों, उसके सदस्यों और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने चाहिए जो ऐसे आतंकवादियों को प्रायोजित और आश्रय दे रहे हैं। ऐसे देशों को दी जाने वाली सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सहायता को आतंकवादी नेटवर्कों, उनके ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और नष्ट करने की दिशा में उनके कार्यों पर निर्भर किया जाना चाहिए। ऐसे राष्ट्रों को आतंकवादियों का समर्थन करने से रोकने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करना आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रणनीति का एक अनिवार्य तत्व है।

> दक्षिण और मध्य एशिया में मजबूत स्वदेशी और सूफी सामग्री के साथ पारंपरिक और उदारवादी इस्लामी मान्यताएं और प्रथाएं कट्टरपंथी वहाबी विचारधाराओं और प्रथाओं के बिल्कुल विपरीत हैं जो अन्य संस्कृतियों और समूहों के प्रति असहिष्णु हैं।

- आतंकवादी संगठनों, उनके सदस्यों, प्रायोजकों/दानदाताओं और सहानुभूति रखने वालों से संबंधित बैंक खातों, चल और अचल संपत्तियों सहित सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए और एक अंतरराष्ट्रीय कोष में जमा किया जाए, जैसा कि 8 अक्तूबर 2004 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1566 द्वारा सुझाव दिया गया था। आतंकवादियों के पीड़ितों और उनके परिवारों को संबंधित सरकारी उपायों के अलावा, इस प्रकार सृजित निधि से राहत और पुनर्वास प्रदान किया जाना चाहिए।

- आतंकवादी समूहों, उनके ठिकानों और अवसंरचना को पकड़ने और नष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और जब आतंकवादी अन्य देशों में अपने अड्डों से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हों तो भी उनका अनुसरण किया जाए।

- दूसरे के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि के लिए एक राष्ट्र के क्षेत्र का उपयोग न करने के सिद्धांत को

सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

- विभिन्न प्रकार के आतंकवादी अपराधों से संबंधित विधायी और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए ताकि आतंकवादियों के शीघ्र परीक्षण, अभियोजन और निवारक सजा सुनिश्चित की जा सके।

- स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज को अपने सामाजिक समर्थन को प्रेरित करने और एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसमें ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाए।

> दक्षिण और मध्य एशिया में पारंपरिक, उदारवादी और उदार मुसलमानों के मूक बहुमत, जो सहिष्णुता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के अनुसार इस्लाम का अभ्यास करते हैं, को अपनी चुप्पी छोड़ने और चरमपंथियों के खिलाफ खुद को मजबूत करने और संगठित करने की आवश्यकता है।

- मीडिया को आतंकवादी गतिविधियों और संबंधित विचारधाराओं के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के बजाय आतंकवादी गतिविधियों के अपने कवरेज में संतुलन बनाना चाहिए।

- आतंकवादियों और उनके प्रायोजक/शरण देने वाले देशों को परमाणु सामग्री और उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच से वंचित करने की आवश्यकता है, ताकि आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग करने और तबाही मचाने की किसी भी संभावना को टाला जा सके। इसका अर्थ उन देशों में परमाणु सामग्री और संबंधित प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करना और समाप्त करना है जो आतंकवादियों को शरण देने/प्रायोजित करने के लिए जाने जाते हैं।

धार्मिक अतिवाद का मुकाबला करना

दक्षिण और मध्य एशिया में सुदृढ़ स्वदेशी और सूफी सामग्री के साथ पारंपरिक और उदारवादी इस्लामी मान्यताएं और प्रथाएं कट्टरपंथी वहाबी विचारधाराओं और प्रथाओं के बिल्कुल विपरीत हैं जो अन्य संस्कृतियों और समूहों के प्रति असहिष्णु हैं। जिहादी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की आधुनिक अवधारणा से सहमत नहीं हैं। एक जिहादी के लिए, इस्लाम भौगोलिक सीमाओं, जातीयताओं, पंथ, नस्ल और अन्य सभी भेदों से परे है। धार्मिक कट्टरपंथियों का ध्यान व्यक्तियों के सुधार के बजाय राष्ट्र का इस्लामीकरण रहा है। सिद्धांत रूप में, इस्लाम में जिहाद एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए था जहां गरीबों और वंचितों के साथ निष्पक्ष और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जिहाद को *जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जमात-उत-दावा* (जेयूडी), *हरकत-उल-जिहाद-उल-इस्लामी* (हूजी), *हरकत-उल-मुजाहिदीन* (एचयूएम) आदि जैसे चरमपंथी आतंकवादी समूहों द्वारा *कितल* (हिंसा) में बदल दिया गया है,

जो इस क्षेत्र में हिंसा और आतंकवाद में सबसे आगे रहे हैं।

चरमपंथी बंदूक की नोक पर अपने आदेशों को लागू करने, *ज़ियारतों* (धर्मस्थलों) और सूफियों की पूजा करने, मनोरंजन के स्थानों को बंद करने, संगीत और ललित कलाओं को बाहर रखने, *हदीस* या परंपरा का सख्ती से पालन करने, सभी स्तरों पर मुस्लिम दिमाग को उकसाने, धर्म और राजनीति को अनिवार्य रूप से एक-दूसरे का पूरक बनाने और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकीकरण की उपलब्धियों को नकारने पर जोर देते हैं। शराब, नृत्य, संगीत, अदालतें, न्यायपालिका, बैंक ब्याज अर्जित करना और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और उदार व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चीजों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती है और गैर-इस्लामी घोषित किया जाता है। विडंबना यह है कि कट्टरपंथी चरमपंथियों को घृणा का प्रचार करने और अभ्यास करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का आह्वान करके एक स्वतंत्र समाज में काम करना आसान लगता है। यह कट्टर *मदरसों* में वैचारिक प्रशिक्षण, पालन-पोषण और ब्रेनवॉश है जो युवा ग्रहणशील दिमागों को ढालता है और आकार देता है। एक प्रमुख पाकिस्तानी विद्वान डॉ परवेज हुडभॉय को उद्धृत करने के लिए, "पाकिस्तानी बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा त्रुटिपूर्ण है और चरमपंथ, असहिष्णुता और अज्ञानता को प्रोत्साहित करती है"।

आतंकवाद जब *जिहाद* की आग और उत्साह के साथ मिश्रित होता है तो यह एक घातक मिश्रण बन जाता है जो दक्षिण और मध्य एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। कट्टरपंथी और हिंसक धार्मिक आंदोलनों का उदय धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राजनीति, बहुलवादी सामाजिक व्यवस्था, अंतर-धार्मिक सद्भाव, सुरक्षा और क्षेत्र में राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर चुनौती है। अब समय आ गया है कि शिक्षाविद, मीडिया, नागरिक समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पारंपरिक इस्लाम और जिहादियों और उनके आकाओं द्वारा प्रतिपादित इस्लाम के बीच अंतर करें। दक्षिण और मध्य एशिया में पारंपरिक, उदारवादी और उदार मुसलमानों के मूक बहुमत, जो सहिष्णुता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के अनुसार इस्लाम का अभ्यास करते हैं, को अपनी चुप्पी छोड़ने और चरमपंथियों के खिलाफ खुद को सुदृढ़ करने और संगठित करने की आवश्यकता है। अपनी ओर से, सरकारों और धर्मनिरपेक्ष समाजों को अंतर-धार्मिक सद्भाव और संवाद को प्रोत्साहित करने के अलावा स्वदेशी, पारंपरिक और विविध इस्लामी प्रथाओं और संस्थानों को संरक्षित करने, बहाल करने और जोर देने में मदद करने की आवश्यकता है।

यूनेस्को के संविधान को याद किया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि "चूंकि युद्ध पुरुषों के दिमाग में शुरू होते हैं, इसलिए यह पुरुषों के दिमाग में है कि शांति की रक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए"। इसलिए शांति की लड़ाई वैचारिक धरातल पर लड़ी जानी है। अधिकांश *मदरसे* युवा छात्रों के दिमाग में इस्लाम के चरमपंथी, विस्मयादिबोधक, अधिनायकवादी और वर्चस्ववादी संस्करण को विकसित करने में लगे हुए हैं, कुरान की आयतों और *हदीस* परंपराओं की गलत व्याख्या करके, *जिहाद, किताल, खिलाफत, हकीमियत-ए-इलाह* (पृथ्वी पर भगवान का शासन) और *घलबा-ए-इस्लाम* (इस्लामी विश्वास की सर्वोच्चता) के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में संशोधित और पुनर्गठित पाठ्यक्रम,

पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से युवा पीढ़ी को आधुनिक, उदार, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे मौजूदा लोगों को प्रतिस्थापित किया जा सके जो घृणा और बंदूक संस्कृति से भरे हुए हैं। सुन्नी इस्लाम के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण स्थल जामिया-अल-अजहर के प्रमुख शेख अहमद अल तैयब के 22 फरवरी 2015 के बयान पर ध्यान देना संतुष्टिदायक है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम दुनिया में धार्मिक अतिवाद के प्रसार को रोकने के लिए इस्लामी शिक्षा में सुधार का आह्वान किया था। उन्होंने आतंकवाद को 'कुरान और हदीस की गलत व्याख्या' से जुड़ी चरमपंथी विचारधारा की उपज बताया। वर्ष 2014 में, 120 मुस्लिम विद्वानों ने आईएस नेता अबू बक्र अल-बगदादी को पत्र लिखकर कहा कि उसने कुरान, शास्त्रीय शिक्षा और वर्तमान युग के संदर्भ की अनदेखी करके इस्लाम का गलत अर्थ निकाला है। *मदरसों* को विनियमित, पुनर्गठित करने और नए उदार शैक्षिक ढांचे के दायरे में लाने की आवश्यकता है। एक बार जब जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीय, जातीय या सामाजिक मूल के आधार पर असहिष्णुता, घृणा और भेदभाव समाप्त हो जाएगा, तो शांति का पालन किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, उत्सव, साहित्य के प्रकाशन आदि। सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए बेहतर अंतर-विश्वास और अंतर-सांस्कृतिक समझ लाने के लिए नियमित रूप से संगठित होने की आवश्यकता है।

नफरत की वकालत और उकसावे पर रोक लगाई जानी चाहिए और इसे अपराध घोषित किया जाना चाहिए। बढ़ते अतिवाद और कट्टरता को खत्म करने के लिए, जो घृणा अपराधों और हिंसा का कारण बनता है, राष्ट्रों और नागरिक समाज को मीडिया, शिक्षा, जमीनी समुदायों और युवाओं के साथ बातचीत के माध्यम से सामाजिक सद्भाव और एकीकरण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। धार्मिक समूहों और समुदायों की भागीदारी के साथ अंतरधार्मिक और अंतर-सांस्कृतिक संवाद असहिष्णुता, अतिवाद और हिंसा के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया जो समुदायों और नेटवर्क के बीच सूचना अभिव्यक्ति, संवाद, शिक्षा, ज्ञान साझा करने के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी मंच प्रस्तुत करते हैं, वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग किया जा सकता है। एससीओ युवाओं और बच्चों को वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ठोस और समन्वित अभियान शुरू करके इस संबंध में कदम उठा सकता है, विशेष रूप से उन देशों में जहां धार्मिक चरमपंथी और आतंकवादी समूह चरमपंथी विचारधाराओं और विकृत विश्व दृष्टिकोण के साथ अपने कैडरों की भर्ती करने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, उत्सव, साहित्य के प्रकाशन आदि में व्यस्त हैं। सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए बेहतर अंतर-विश्वास और अंतर-सांस्कृतिक समझ लाने के लिए नियमित रूप से संगठित होने की आवश्यकता है।

एससीओ ने मार्च 2009 में मास्को में अफगानिस्तान पर एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया था। एससीओ के सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों के अलावा, प्रतिभागियों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के उप सहायक सचिव और यूरोपीय संघ, नाटो, ओएससीई, सीएसटीओ, ओआईसी आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। इस तरह की उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी ने अफगानिस्तान में एससीओ की भूमिका को मान्य किया।

अफगानिस्तान इंब्रोग्लियो और एससीओ

जब 1990 के दशक में ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले ट्रांस-रीजनल आतंकवादी नेटवर्क अल कायदा ने अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के आधार के रूप में बदल दिया, तो यह पड़ोस की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया, विशेष रूप से नए स्वतंत्र मध्य एशियाई देशों के लिए। 9/11 के बाद, जब अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध शुरू किया गया था, तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य एशियाई गणराष्ट्रों ने क्रमशः कर्शी खानाबाद, मानस और दुशांबे में आईएसएएफ बलों को हवाई अड्डे की सुविधा प्रदान की। कजाकिस्तान ने ओवरफ्लाईंग अधिकार, मरम्मत और ईंधन भरने की सुविधाएं दीं। इसके अलावा, मध्य एशियाई गणराष्ट्र अफगानिस्तान में मानवीय प्रयासों में शामिल हो गए। अफगानिस्तान में हामिद करजई के नेतृत्व में अंतरिम प्रशासन की स्थापना के तुरंत बाद, एससीओ ने जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अपनी बैठक में औपचारिक रूप से "आतंक, युद्ध, ड्रग्स और गरीबी से मुक्त एक नए, स्थिर अफगानिस्तान के निर्माण" का स्वागत किया, और "पूरे अफगान लोगों के हित में व्यापक रूप से प्रतिनिधि सरकार बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने" के लिए तत्परता व्यक्त की[3]। मॉस्को में आयोजित 2003 का अगला एससीओ शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान से नशीली दवाओं की तस्करी के खतरे के बारे में चिंतित था। सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की कि "संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अफगान ड्रग्स खतरे के व्यापक निष्प्रभावीकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाए"[4]। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने 2004 में ताशकंद में आयोजित एससीओ के ताशकंद शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन में, सदस्य राष्ट्रों ने 17 जून 2004 को अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वय भूमिका को मान्यता देते हुए एक घोषणा जारी की। उन्होंने सुरक्षा, शांति और व्यवस्था हासिल करने और अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाने की दृष्टि से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में प्रयासों को समन्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 2005 में आयोजित अस्ताना शिखर सम्मेलन में, एससीओ सदस्यों ने अफगानिस्तान से निकलने वाली नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

एससीओ क्षेत्र के लिए अफगानिस्तान में स्थिरता के निकट और दीर्घकालिक महत्व को स्वीकार करते

हुए, संगठन ने 2005 में अस्ताना में अपनी बैठक में एक प्रोटोकॉल अपनाकर एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह (एसएसीजी) बनाया। अफगानिस्तान और एससीओ के बीच औपचारिक सहयोग 2005 में एसएसीजी की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद, चरमपंथ और नशीली दवाओं की तस्करी से लड़ना था। एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद जारी 16 अगस्त 2007 की बिश्केक घोषणा में, सदस्य देशों ने "अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले नशीली दवाओं के खतरे और मध्य एशियाई क्षेत्र पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की"। उन्होंने अफगानिस्तान के चारों ओर 'मादक पदार्थ विरोधी सुरक्षा बेल्ट' को सचेत रूप से सुदृढ़ करने का आह्वान किया। अगस्त 2008 में एससीओ के दुशांबे शिखर सम्मेलन में एक बार फिर अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। सदस्य देशों ने "अफगानिस्तान में विकास, नशीली दवाओं की तस्करी की बढ़ती मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, जिसके कारण ऐसी चुनौतियों और खतरों के मूल्यांकन, रोकथाम और प्रतिक्रिया के संयुक्त तंत्र के निर्माण की आवश्यकता थी"। 27 अगस्त 2008 को जारी अपनी घोषणा में, एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जनादेश पर अफगानिस्तान में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएसएएफ) से अफगानिस्तान सरकार के समन्वय में अफगान नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी का मुकाबला करने के कार्य पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया।

एससीओ ने मार्च 2009 में मास्को में अफगानिस्तान पर एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया था। एससीओ के सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों के अलावा, प्रतिभागियों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के उप सहायक सचिव और यूरोपीय संघ, नाटो, ओएससीई, सीएसटीओ, ओआईसी आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। इस तरह की उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी ने अफगानिस्तान में एससीओ की भूमिका को मान्य किया। अफगानिस्तान और क्षेत्र में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, सम्मेलन ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण, समृद्ध और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान को प्राप्त करने के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। इसने आतंकवाद और ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी के संकट का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अफगान सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया[5]। इस सम्मेलन के दौरान एससीओ के सदस्य देशों और अफगानिस्तान द्वारा जारी एक अन्य संयुक्त बयान में एससीओ दवा नियंत्रण सहयोग तंत्र में और सुधार के साथ-साथ एससीओ सदस्य देशों और क्षेत्र के अन्य देशों की दवा विरोधी एजेंसियों के बीच व्यावहारिक सहयोग की योजनाओं के विस्तार का आह्वान किया गया।

15-16 जून 2009 को आयोजित येकातेरिनबर्ग शिखर सम्मेलन में, एससीओ के सदस्य देशों ने "अवैध नशीली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से संबंधित अफगानिस्तान में जटिल स्थिति पर अपनी गंभीर चिंता" को दोहराया। 10-11 जून, 2010 को ताशकंद में आयोजित अगले एससीओ शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान में स्थिति में निरंतर गिरावट और उस देश से उत्पन्न आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों पर भी ध्यान दिया गया, जिसने इस क्षेत्र के लिए

गंभीर खतरे पैदा किए। एससीओ के सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में स्थिति में मध्यस्थता करने में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी भूमिका के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। यह कहते हुए कि अकेले सैन्य साधन अफगानिस्तान के मुद्दे को हल नहीं कर सकते हैं, एससीओ के सदस्य देशों ने "वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है और अफगान लोग भाग लेते हैं। एससीओ ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में सभी जातीय समूहों के समय-सम्मानित इतिहास, राष्ट्रीय मूल और पारंपरिक धार्मिक मूल्यों का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। 10-11 जून, 2011 को अस्ताना में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में एससीओ के पांच सदस्य देशों के प्रमुखों के अलावा भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी भाग लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद जारी अपनी घोषणा में, एससीओ ने "एक स्वतंत्र, तटस्थ, शांतिपूर्ण और समृद्ध देश के रूप में अफगानिस्तान के विकास का समर्थन किया"।

> जैसा कि रूसी संघ के राजदूत विताली वोरोबिएव ने कहा: "किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ 1990 के दशक के अंत में अफगानिस्तान संघर्ष से आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के तत्काल खतरों के जवाब के रूप में बनाया गया था। एससीओ का विचार उनसे निपटने के लिए एक क्षेत्रीय गठबंधन की सामूहिक मांग से पैदा हुआ था।

6-7 जनवरी 2012 को आयोजित एससीओ के बीजिंग शिखर सम्मेलन में, अफगानिस्तान जो अधिकांश एससीओ राष्ट्रों का पड़ोसी है, को एससीओ के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। अफगानिस्तान के संबंध में एससीओ के सदस्यों का आम विचार यह रहा है कि अफगान समस्या का सैन्य समाधान नहीं हो सकता है और एससीओ राष्ट्रों को अफगानिस्तान को आर्थिक, राजनीतिक और अफगान लोगों की भागीदारी के साथ विकसित करने में मदद करनी चाहिए। एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह को पुनर्जीवित किया गया था जब यह 11 अक्तूबर 2017 को मास्को में उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर मिला था। प्रतिनिधियों ने राजनीतिक परामर्श और बातचीत के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने के लिए अफगानिस्तान सरकार और लोगों के प्रयासों का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया। सदस्यों ने क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों और खतरों और अफगानिस्तान को एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण के लिए सहायता पर विचारों का आदान-प्रदान किया। एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह ने 28 मई 2018 को बीजिंग में एससीओ सदस्य राष्ट्रों और इस्लामिक गणराष्ट्र अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक और बैठक आयोजित की। एससीओ के महासचिव राशिद अलीमोव के हवाले से कहा गया, "बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति, शांति प्रक्रिया बहाल करने के लिए अफगानिस्तान की सरकार और लोगों द्वारा किए गए प्रयासों को सहायता और एससीओ-अफगानिस्तान सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर गहराई से विचारों का आदान-प्रदान देखा गया। बयान में कहा गया है, "एससीओ सदस्य देशों के नेता अफगानिस्तान

की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ अफगान सरकार और लोगों के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता में एकमत थे, क्योंकि वे अपने देश को बहाल करने और लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। बयान में कहा गया है, "यह महसूस किया गया कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की गारंटी देने में संयुक्त राष्ट्र की समन्वय भूमिका के साथ सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राष्ट्र शासन और विकास समस्याओं के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण लंबे समय से प्रतीक्षित परिणाम ला सकता है।

एक अफगान राजनयिक और एक शिक्षाविद, एम अशरफ हैदरी ने इसे संक्षेप में कहा: "पिछले 17 वर्षों में, हमने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग से सीखा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईमानदार, परिणाम-संचालित क्षेत्रीय सहयोग के बिना अफगानिस्तान में शांति को सुरक्षित करना मुश्किल होगा।

जैसा कि रूसी संघ के राजदूत विताली वोरोबिएव ने कहा[6]: "उन्होंने कहा, 'किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ का गठन 1990 के दशक के अंत में अफगानिस्तान संघर्ष से आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के तत्काल खतरों के जवाब में किया गया था। एससीओ का विचार उनसे निपटने के लिए एक क्षेत्रीय गठबंधन की सामूहिक मांग से पैदा हुआ था। इसी तरह के विचार एससीओ के पूर्व महासचिव मूरतबेक इमानलीव ने 2010 में बिश्केक में एक साक्षात्कार के दौरान व्यक्त किए थे[7]: "अफगानिस्तान एससीओ के सदस्य देशों के सहयोग का मुख्य कारण है और सभी देशों के लिए समस्या है, जो आम हित का एकमात्र विषय है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव के अनुसार[8], "सबसे पहले, अफगानिस्तान आतंकवादियों का मुख्य आधार बना हुआ है, जिसमें आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों से संबंधित लोग भी शामिल हैं, जिनका लक्ष्य मध्य एशिया में स्थिति को अस्थिर करना, मौजूदा राजनीतिक शासन को गिराना और अपनी सीमाओं के भीतर मुस्लिम खलीफा बनाना है। दूसरा, अफगानिस्तान कच्चे अफीम के उत्पादन के लिए मुख्य आधार बना हुआ है और मध्य एशियाई राष्ट्रों के माध्यम से वैश्विक बाजारों में हेरोइन और अन्य दवाओं का मुख्य आपूर्तिकर्ता भी है। गठबंधन सेना की वापसी के बाद, कट्टरपंथियों ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में आत्मविश्वास महसूस करना शुरू कर दिया, और अफगानिस्तान के उत्तर में एक ब्रिजहेड स्थापित किया, जहां से चरमपंथी मध्य एशिया के पड़ोसी देशों में प्रवेश करते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा बढ़ गया है।

एक अफगान राजनयिक और एक शिक्षाविद, एम अशरफ हैदरी ने इसे संक्षेप में कहा[9]: "पिछले 17 वर्षों में, हमने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग से सीखा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईमानदार, परिणाम-संचालित क्षेत्रीय सहयोग के बिना अफगानिस्तान में शांति सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। वास्तव में, आतंकवाद को हराने और अफगानिस्तान पर शांति हासिल करने में सामूहिक विफलता के

प्रतिकूल प्रभाव होंगे, जो आसानी से सीमाओं को पार कर सकते हैं, क्षेत्र और दुनिया को बड़े पैमाने पर अस्थिर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

भले ही अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ युद्ध बीस वर्ष पहले शुरू किया गया था, लेकिन बढ़ती असुरक्षा और बिगड़ती सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण अफगानिस्तान में स्थिति अस्थिर बनी हुई है। स्थिति का एक अन्य पहलू यह है कि यूएनओडीसी के 2018 के अफगानिस्तान अफीम सर्वेक्षण के अनुसार, अफगानिस्तान में कुल अफीम अफीम की खेती के क्षेत्र में 2014 के स्तर की तुलना में 263,000 हेक्टेयर में 17 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 39,000 हेक्टेयर की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। अधिकांश अफीम की खेती दक्षिणी क्षेत्र (69%) में हुई, इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र (12%), पूर्वी क्षेत्र (8%) और उत्तरी क्षेत्र (7%) थे। एससीओ के सदस्य देशों ने 10 जून 2018 को वर्ष 2018-23 में एंटी-ड्रग रणनीति को मंजूरी दी, जिसमें अफगानिस्तान से निकलने वाले नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के उपायों को रेखांकित किया गया। अफगानिस्तान में वर्तमान तालिबान शासन ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि इन प्रतिबंधों का प्रभाव देखा जाना बाकी है।

इसलिए अफगानिस्तान में स्थायी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी दुविधा को छोड़ने और अफगानिस्तान में और उसके आसपास आतंकवाद और चरमपंथ को रोकने के लिए एक ठोस रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है, उनके धन, हथियार, रसद और प्रशिक्षण और वैचारिक प्रेरणा के स्रोतों को रोककर भारतीय नीति अफगानिस्तान में भौतिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, मानव संसाधन और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति में मदद करने की रही है। भारत भारतीय संस्थानों में अपनी शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए सालाना 1,000 से अधिक अफगान छात्रों को प्रायोजित करता है। भारत ने कुछ सौ वाहन, कुछ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर प्रदान किए, नए संसद परिसर, सलमा बांध का निर्माण किया, जिसमें 75,000 हेक्टेयर खेत की सिंचाई के अलावा 42 मेगावाट बिजली की क्षमता है, डेलाराम-जरांज रोड, टर्मेज़ से काबुल तक ट्रांसमिशन लाइन और 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी स्कूल हैं। सैकड़ों लघु और मध्यम विकास परियोजनाएं भी शुरू की गईं। भारत 2001 से 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्रीय दाता और विश्व स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा दाता है।

तालिबान के अधिग्रहण के बाद, अफगानिस्तान और उसके लोगों का भविष्य विविध जातीय, क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संतुलित, समावेशी और स्थिर सरकार के उद्भव पर टिका है। भारत अफगान लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने का समर्थन करता है। भारत ने अफगानिस्तान में चुनौतीपूर्ण मानवीय स्थिति को देखते हुए 11 दिसंबर 2021 को काबुल में चिकित्सा आपूर्ति की पहली किश्त हवाई मार्ग से पहुंचाई थी। भारत ने पाकिस्तान के माध्यम से भूमि मार्ग द्वारा अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति करने की भी प्रतिबद्धता जताई है, जिसने अफगान

ट्रकों को वाघा-अटारी सीमा से खेप ले जाने की अनुमति दी है। दिसंबर 2021 के मध्य तक, भारत ने अफगानिस्तान से 669 लोगों को निकाला था, जिसमें 448 भारतीय और अफगान हिंदू और सिख अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों सहित 206 अफगान शामिल थे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से 438 भारतीयों सहित 565 लोगों को निकाला गया था।

> ध्वस्त सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय व्यापार और यातायात के पारगमन केंद्र के रूप में अफगानिस्तान का विकास, अफगानिस्तान में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को वापस पटरी पर लाने में मदद करेगा, हालांकि यह प्रक्रिया बोझिल और लंबी है।

ईरान सहित एससीओ के सदस्य देश अफगानिस्तान से अपने देशों में चरमपंथियों, सशस्त्र आतंकवादियों, शरणार्थियों, ड्रग्स, हथियारों और संगठित अपराध की सीमा पार आवाजाही को लेकर चिंतित हैं। ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित कई देश, जिनकी अफगानिस्तान के साथ भौतिक सीमाएं हैं, अफगानिस्तान से अपने क्षेत्रों में संघर्ष, आतंकवाद और उग्रवाद के फैलने के बारे में चिंतित हैं। चूंकि, कई देश शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का हिस्सा हैं, इसलिए यह इन देशों को अफगानिस्तान पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और चुनौती से निपटने के लिए एक आम रणनीति तैयार करने के लिए एक अच्छा और व्यवहार्य मंच प्रदान करता है। अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति के बीच, अफगानिस्तान पर एससीओ विदेश मंत्रियों के संपर्क समूह ने जुलाई 2021 के मध्य में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में बैठक की। यहां भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हिंसा और आतंकवादी हमलों को समाप्त करने, राजनीतिक वार्ता के माध्यम से संघर्ष के समाधान और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया कि पड़ोसी देशों को आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से खतरा न हो[10]। एससीओ और आरएटीएस की अफगानिस्तान सहित सदस्य देशों के बीच निश्चित समझौतों/व्यवस्थाओं पर काम करके एक विशिष्ट भूमिका है, (i) द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौतों पर बातचीत करना, (ii) क्षेत्र में सक्रिय कट्टरपंथी चरमपंथियों और आतंकवादियों का नियमित रूप से जायजा लेना, और ऐसी जानकारी का आदान-प्रदान करना (iii) आतंक के वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान करना और इन चैनलों को अवरुद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। (iv) *जिहाद* के नाम पर आतंकवादियों और चरमपंथियों की घृणा की विचारधारा को खारिज करने के लिए इस्लामी पादरियों/उलेमाओं से सहयोग लेना और उनका सहयोग लेना।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पारगमन और व्यापार को बढ़ावा देना

एससीओ और इसके सदस्य देश अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और इसकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के इच्छुक हैं। ध्वस्त सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय व्यापार और यातायात के पारगमन केंद्र के रूप में अफगानिस्तान का विकास, अफगानिस्तान में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को वापस पटरी पर लाने में मदद करेगा, हालांकि यह प्रक्रिया बोझिल और

लंबी है। जबकि मध्य एशिया का भू-रणनीतिक महत्व और इस क्षेत्र में बड़ी शक्ति के हित इसे बहुत महत्व का क्षेत्र बनाते हैं, गैर-आधिपत्य इरादों की भावना के साथ इस क्षेत्र में वास्तविक साझेदारी में संलग्न होने की आवश्यकता है। भू-राजनीतिक खेल से भू-सांस्कृतिक और भू-आर्थिक सहयोग के प्रतिमान की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। मध्य एशिया, अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया और पड़ोसी देशों ईरान, रूस और चीन के बीच एक तीव्र सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्थिरता लाने के अलावा व्यापार और आर्थिक सहयोग में बहुत वृद्धि करेगा। संवादों, ज्ञान साझा करण तंत्र और द्विपक्षीय परिवहन संबंधों के अलावा, सभी संबंधित देशों को समान अवसर प्रदान करके ऊर्जा पारगमन और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक ढांचे की आवश्यकता है।

> भारत अफगान ताजे और सूखे मेवों और कालीनों के लिए एक विशाल पारंपरिक बाजार प्रदान करता है, जो अफगान अर्थव्यवस्था के नुकसान के लिए अप्रयुक्त रहता है, क्योंकि अफगान ट्रकों को भारतीय सामान वापस ले जाने के लिए उन पर रोक के कारण वाघा से खाली लौटना पड़ता है।

> अफगानिस्तान-पाकिस्तान पारगमन व्यापार समझौते में भारत को शामिल करने और सीएआर तक इसके विस्तार से न केवल दक्षिण एशिया में उच्च स्तर का क्षेत्रीय सहयोग और विकास होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में समृद्धि और शांति भी आएगी।

अफगानिस्तान महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह उत्तर में मध्य एशिया और दक्षिण में दक्षिण एशिया के बीच एक भूमि पुल प्रदान करता है। भारत मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच माल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान (अश्गाबात समझौता)[11] के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना के समझौते का सदस्य है। जबकि पाकिस्तान और कजाकिस्तान पहले ही अश्गाबात समझौते में शामिल हो गए थे, समझौते में भारत 3 फरवरी 2018 को शामिल हुआ। यह मध्य एशिया के साथ भारत के संपर्क में विविधता लाएगा और चाबहार बंदरगाह, आईएनएसटीसी में भारतीय उपस्थिति के साथ-साथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भविष्य की व्यवस्था/समझौतों का पूरक होगा।

एससीओ मध्य एशियाई गणराष्ट्रों, रूस और चीन के बीच बहुपक्षीय सहयोग के एक प्रभावी क्षेत्रीय संस्थागत तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं, इसलिए सदस्य देशों के बीच

सहयोग बढ़ाने की संभावना है। पाकिस्तान ऊर्जा संसाधनों के आयात और भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत को दिए जाने वाले ओवरलैंड मध्य एशिया-अफगानिस्तान-पाकिस्तान गलियारे को अवरुद्ध करने की अपनी नीति पर कायम रहा है। हालांकि, हाल ही में, पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान को गेहूं के रूप में अपनी मानवीय सहायता भेजने के लिए पारगमन पहुंच की अनुमति दी है। अफगानिस्तान-पाकिस्तान व्यापार पारगमन समझौता, जिसे 19 जुलाई 2010 को अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की उपस्थिति में अंतिम रूप दिया गया था, जबकि अफगान ट्रकों को भारत में आगे भेजने के लिए वाघा सीमा पर सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी, इन ट्रकों को अफगानिस्तान में भारतीय सामान वापस ले जाने की अनुमति नहीं देता है। यह समझौता पाकिस्तान को इस्लाम किला और जरांज सीमा के माध्यम से ईरान तक, हेरातन के माध्यम से उजबेकिस्तान तक, अली खानम और शेर खान बंदर क्रॉसिंग के माध्यम से ताजिकिस्तान तक, अकीना और तोरघुंडी सीमा क्रॉसिंग के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान तक और सोस्ट/ताशकुरघन सीमा के माध्यम से चीन तक पहुंच प्रदान करता है[12]। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के तीन बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान की गई है: पोर्ट कासिम, ग्वादर और कराची बंदरगाह[13]। पाकिस्तानी आयात और निर्यात को तोरखम, गुलाम खान और चमन में सीमा क्रॉसिंग के माध्यम से अफगानिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अप्रैल 2015 में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान पाकिस्तान से आग्रह किया था कि वह अफगान ट्रकों को वाघा से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर अटारी में भारतीय जांच चौकी तक जाने की अनुमति दे[14]। गनी ने पाकिस्तान से कहा कि वह 2011 में हस्ताक्षरित अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट (एपीटीटीए) में सहमत 'राष्ट्रीय उपचार' खंड को स्वीकार करे, जो दोनों देशों को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं तक समान पहुंच प्रदान करता है[15]। उन्होंने आगे कहा कि "अगर हमें समान पारगमन पहुंच नहीं दी जाती है, तो हम मध्य एशिया के लिए समान पारगमन पहुंच प्रदान नहीं करेंगे[16]। मध्य एशियाई गणराष्ट्रों (सीएआर) को पाकिस्तानी निर्यात इसके कुल निर्यात का लगभग 0.054% है, जबकि सीएआर से पाकिस्तान द्वारा आयात इसके कुल आयात का लगभग 0.05% है[17]। यह वास्तविक व्यापार और इसकी क्षमता के बीच एक बड़े अंतर को दर्शाता है, जिसे भारत और सीएआर के लिए एपीटीटीए के दायरे का विस्तार करने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भारत अफगान ताजे और सूखे मेवों और कालीनों के लिए एक विशाल पारंपरिक बाजार प्रदान करता है, जो अफगान अर्थव्यवस्था के नुकसान के लिए अप्रयुक्त रहता है, क्योंकि अफगान ट्रकों को भारतीय सामान वापस ले जाने के लिए उन पर रोक के कारण वाघा से खाली लौटना पड़ता है। इन बाधाओं के बावजूद, भारत अफगान निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है। यद्यपि भारत ने अफगानिस्तान के लिए शुल्क मुक्त बाजार पहुंच की अनुमति दी है[18], लेकिन इसे पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पारगमन पहुंच से वंचित कर दिया गया है। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणराष्ट्र विशाल भारतीय बाजार में ताजे और सूखे फलों की प्रचुर आपूर्ति का निर्यात करने के इच्छुक हैं, जो केवल तभी संभव है जब इन्हें भारतीय वस्तुओं के बदले में अफगानिस्तान-पाकिस्तान-वाघा मार्ग के माध्यम से भारत लाया जाए। हाल ही में, एक भारतीय निजी व्यापारी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से सड़क मार्ग से भारत से उजबेकिस्तान तक 140 टन माल का निर्यात किया, जिसमें ज्यादातर चीनी थी[19]। इस मार्ग में भारत से

पाकिस्तान के कराची बंदरगाह तक आने वाले कार्गो के साथ समुद्र और भूमि माल परिवहन शामिल था। फिर इसे पाकिस्तान के पार और तोरखम सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान में, फिर काबुल, मजार-ए-शरीफ और उज्बेकिस्तान के टर्मेज में ले जाया गया। इससे पहले जुलाई 2021 में, पाकिस्तान और उजबेकिस्तान ने एक पारगमन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उज़्बेक ट्रकों को अफगानिस्तान के माध्यम से सीधे कराची, ग्वादर और बिन कासिम में पाकिस्तानी बंदरगाहों पर माल ले जाने की अनुमति है। यह बहुपक्षीय भारत-पाकिस्तान-अफगानिस्तान-सीएआर पारगमन और व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए अच्छा संकेत है। अफगानिस्तान-पाकिस्तान पारगमन व्यापार समझौते में भारत को शामिल करने और सीएआर तक इसके विस्तार से न केवल दक्षिण एशिया में उच्च स्तर का क्षेत्रीय सहयोग और विकास होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में समृद्धि और शांति भी आएगी।

भारत, मध्य एशिया और एससीओ
संभावनाएं और चुनौतियां

एस. के. पांडे

1991 कई मायनों में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। सोवियत विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व राजनीति में एक नए चरण की शुरुआत की। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और रूस ने अराजक संक्रमण और गिरावट के एक दशक में प्रवेश किया। यह वह वर्ष भी था जब भारत ने आर्थिक सुधारों (एलपीजी के रूप में लोकप्रिय-उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) की शुरुआत की, जिसने इसे एक आर्थिक और राजनीतिक नायक के रूप में विश्व मंच पर पहुंचा दिया[20]। लेकिन 1989 की तियानमेन चौक की घटना के बाद चीन का उदय अधिक शानदार था। डेंग ज़ियाओपिंग के अर्ध-बाजार सुधारों ने चीन की आर्थिक सफलता को प्रेरित किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी लोगों को एक समझौते की पेशकश करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया-एक-पार्टी शासन को स्वीकार करने के बदले में अधिक भौतिक समृद्धि[21]।

एक अन्य महत्वपूर्ण विकास वैश्विक क्षेत्र में एक भू-राजनीतिक क्षेत्र के रूप में पांच स्वतंत्र देशों के साथ मध्य एशिया का उदय था। मध्य एशिया की परिभाषित विशेषता इसका लैंडलॉक स्थान है, जो इस क्षेत्र के देशों के लिए व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए बाहरी दुनिया तक पहुंचने के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर होना अनिवार्य बनाता है। मध्य एशिया कई प्राचीन/मध्ययुगीन सभ्यताओं–चीनी, फारसी, तुर्किक, रूसी और भारतीय के चौराहे पर रहा है और प्रत्येक से तत्वों को आत्मसात किया है। यह कई साम्राज्यों/रियासतों का एक बैठक स्थल और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में यह ज़ारिस्ट रूसी और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यों के बीच तीव्र धक्का-मुक्की का क्षेत्र बन गया। द ग्रेट गेम, जैसा कि मध्य एशिया में एंग्लो-रूसी प्रतिद्वंद्विता को बेहतर जाना जाता है, रोमांच और साज़िश की एक सम्मोहक कहानी थी। पुराना ग्रेट गेम समाप्त हो गया जब ब्रिटेन और रूस ने 1907 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए[22]।

क्षेत्रीय विन्यास

1991 में सोवियत विघटन ने न केवल मध्य एशिया में पांच स्वतंत्र गणराष्ट्रों का उदय किया, बल्कि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नया चरण, जिसे अक्सर न्यू ग्रेट गेम 4 के रूप में वर्णित किया जाता है[23]। इस क्षेत्र का स्थान महान शक्तियों-रूस और चीन (एक पूर्व और दूसरी उभरती महाशक्ति)-और अफगान-पाक क्षेत्र की सीमा पर है-जो 1996 में तालिबान के उद्भव के साथ तेजी से अस्थिर हो गया; और इस क्षेत्र में

महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन और खनिज संसाधनों ने इसे भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया। 9/11 हमले और अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ने अमेरिका को इस क्षेत्र में लाया, जिससे तीनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में चीन का हित कच्चे माल, बाजार और प्रभाव की खोज में निहित है, और इस क्षेत्र पर प्रतिकूल शक्तियों (जैसे अमेरिका) के प्रभुत्व को रोकने की इच्छा और/या विचारधाराओं/आंदोलनों (जैसे धार्मिक चरमपंथियों) जो इसके अशांत उइगर शिनजियांग क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता है। रूस की महत्वाकांक्षा विदेशों में अपने निकट और विशेष रुचि के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने और अपनी दक्षिणी सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र को स्थिर करने की है। भारत, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के अपने उद्देश्य और रणनीतियां हैं। यह तथ्य कि पांच मध्य एशियाई राष्ट्र इन शक्तियों की दया पर निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि सक्रिय प्रतिभागी, यकीनन सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जो अपने हितों को अधिकतम करने के लिए अपने संतुलन कार्यों और चतुराई से पैंतरेबाज़ी खेल रहे हैं। इस प्रकार, यह (कभी-कभी) परस्पर विरोधी हितों, बारीक रणनीतियों और अनिश्चित परिणाम के साथ विभिन्न नायकों का एक जटिल अंतःक्रिया है।

तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, चीन का हित कच्चे माल, बाजारों और प्रभाव की खोज में निहित है, और इस क्षेत्र पर प्रतिकूल शक्तियों (जैसे अमेरिका) के प्रभुत्व को रोकने की इच्छा और/या विचारधाराओं/आंदोलनों (जैसे धार्मिक चरमपंथियों) जो इसके अशांत उइगर शिनजियांग क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता है। रूस की महत्वाकांक्षा विदेशों में अपने निकट और विशेष रुचि के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने और अपनी दक्षिणी सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र को स्थिर करने की है।

> शंघाई फाइव सफल रहा है क्योंकि इसने न केवल 7000 किलोमीटर की सीमा को हल करने में मदद की, बल्कि सदस्य देशों के बीच सद्भावना और विश्वास भी पैदा किया, धार्मिक अतिवाद और कट्टरवाद से उत्पन्न खतरे पर प्रकाश डाला, और एक बहुपक्षीय तंत्र बनाया जिसके माध्यम से सदस्य देश अपनी सामान्य चिंताओं पर चर्चा कर सकते हैं और अपनी गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं।

शंघाई पांच और एससीओ

विवादित चीन-सोवियत सीमा दो कम्युनिस्ट पड़ोसियों-सोवियत संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच तनाव का एक निरंतर स्रोत थी। सोवियत विघटन के बाद चीन और सोवियत रूस के बाद, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक तंत्र बनाने का निर्णय लिया। 26 अप्रैल 1996 को, पांच देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने शंघाई में अपनी साझा सीमाओं के साथ

सुरक्षा और विश्वास-निर्माण उपायों पर चर्चा करने और सीमा विवादों को हल करने के लिए मुलाकात की। इससे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पूर्ववर्ती शंघाई फाइव नामक एक नए बहुपक्षीय क्लब का निर्माण हुआ[24]। शंघाई फाइव सफल रहा है क्योंकि इसने न केवल 7000 किलोमीटर की सीमा को हल करने में मदद की, बल्कि सदस्य देशों के बीच सद्भावना और विश्वास भी पैदा किया, धार्मिक अतिवाद और कट्टरवाद से उत्पन्न खतरे पर प्रकाश डाला, और एक बहुपक्षीय तंत्र बनाया जिसके माध्यम से सदस्य देश अपनी सामान्य चिंताओं पर चर्चा कर सकते हैं और अपनी गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं। शंघाई फाइव की सापेक्ष सफलता को सदस्य देशों के बीच "साझा हितों, अंतर्राष्ट्रीय आचरण के साझा मानदंडों और व्यावहारिक और क्रमिक दृष्टिकोण" के बारे में एहसास के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है[25]। सहयोग के लिए इस क्षेत्रीय बहुपक्षीय तंत्र ने शंघाई सहयोग संगठन के उद्भव के लिए आधार तैयार किया।

> आमतौर पर यह माना जाता है कि एससीओ की प्राथमिक चिंता आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद की तीन बुराइयों के खिलाफ सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा है। हालांकि, संगठित अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी और यहां तक कि साइबर और सूचना युद्ध को शामिल करने के लिए सुरक्षा व्यापक हो सकती है।

2001 एक ऐतिहासिक वर्ष था जिसने वैश्विक राजनीति के स्वरूप को बदल दिया। 9/11 हमलों और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध ने धार्मिक अतिवाद और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उत्पन्न खतरे पर ध्यान केंद्रित किया। एबीएम संधि से अमेरिका की वापसी अमेरिका के एकतरफावाद और रूस की निराशा का संकेत देती है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चीन के शामिल होने से देश की आर्थिक वृद्धि में एक और मील का पत्थर सिद्ध हुआ, जबकि शंघाई में एपेक शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने बीजिंग के राजनयिक कौशल को दिखाया। भारत के लिए, वर्ष की शुरुआत विनाशकारी गुजरात भूकंप के साथ हुई और संसद हमले के साथ समाप्त हुई। यह वह वर्ष भी था जब शंघाई फाइव को एससीओ में बदल दिया गया था, जिसमें उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद की तीन बुराइयों से लड़ने की प्रतिबद्धता थी। तालिबान की हार ने चरमपंथ और आतंकवाद के एक स्रोत को खत्म कर दिया, लेकिन अमेरिका-पाक संबंधों ने भारत के लिए एक चुनौती पैदा कर दी। काबुल में लोकतांत्रिक शासन ने भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ जुड़ने का अवसर पैदा किया। यह वह समय भी था जब भारत रूस और ईरान के साथ मिलकर उत्तर-दक्षिण गलियारे को लॉन्च करके कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा था।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 15 जून 2001 को शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान गणराष्ट्र, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज गणराष्ट्र, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराष्ट्र और उजबेकिस्तान गणराष्ट्र

(जो शंघाई पांच तंत्र का हिस्सा नहीं था) द्वारा बनाया गया था। यह एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय[26] संगठन है। जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान एससीओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। यह वैधानिक दस्तावेज एससीओ की संरचना और प्रमुख गतिविधियों के साथ लक्ष्यों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। संगठन का उद्देश्य है: "सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसी को सुदृढ़ करना; राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना; क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना; और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहा है[27]।

आमतौर पर यह माना जाता है कि एससीओ की प्राथमिक चिंता आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद की तीन बुराइयों के खिलाफ सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा है। हालांकि, संगठित अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी और यहां तक कि साइबर और सूचना युद्ध 9 को शामिल करने के लिए सुरक्षा व्यापक हो सकती है[28]। एससीओ का संयुक्त राष्ट्र के साथ व्यापक सहयोग है। यह 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक बन गया[29]। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों के विभाग (डीपीपीए) ने 2017 में बीजिंग में एससीओ के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया। इसकी स्थापना के बाद से, चीन और रूस एससीओ के दो स्तंभ हैं और उन्होंने काफी हद तक इसके एजेंडे और कामकाज को तय किया है।

एससीओ में रूस-चीन: सहयोग और प्रतिस्पर्धा

1990 के दशक में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ और बाद में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की पहल और मुक्त व्यापार व्यवस्था समझौतों की झड़ी लग गई। चीन वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है, और आज यह इस तरह की पहल का एक सक्रिय भागीदार और समर्थक है। यह मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को वैश्विक व्यापार के लिए खोलने का एक और तरीका मानता है, जो चीनी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगा। एससीओ एक ऐसा मंच है जिसका उपयोग बीजिंग एफटीए और एससीओ विकास बैंक बनाकर पड़ोसी देशों को अपने औद्योगिक उत्पादों, श्रम और पूंजी का निर्यात करने के लिए करना चाहता है। हालांकि, कई सदस्य राष्ट्रों के बीच अपने घरेलू बाजारों को आयातित चीनी सामानों से अभिभूत होने के बारे में चिंता के कारण, ऐसे प्रस्ताव आगे नहीं बढ़े हैं[30]।

रूस, जो मध्य एशिया को विशेष रुचि का क्षेत्र (विदेश के पास) मानता है, मध्य एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति और एससीओ के प्रभुत्व से आशंकित है, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में। चीन के साथ अपनी कमजोरी को देखते हुए, मॉस्को ने एससीओ मुक्त आर्थिक क्षेत्र, एक एससीओ विकास बैंक और एससीओ विकास कोष बनाने के चीनी प्रस्तावों और किसी भी पहल का विरोध किया है जो रूसी प्रायोजित यूरेशियन

इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) को कमजोर करेगा। रूस ने एससीओ के मध्य एशिया फोकस 12 को कमजोर करने के लिए नए सदस्यों (जैसे भारत) को शामिल करने का समर्थन किया है[31]।

> रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप, चीन और यूरोपीय संघ के बीच आपूर्ति मार्गों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए, चीन मध्य एशिया के माध्यम से विकल्पों पर काम कर रहा है, जिसमें रूस इस रणनीति में सह-भागीदार के रूप में है। यह कभी-कभी "मध्य एशिया में रूस और चीन की शांत प्रतियोगिता" के रूप में जाना जाता है।

एससीओ एकमात्र प्रारूप नहीं है जिसके माध्यम से चीन मध्य एशिया में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इसने इस क्षेत्र के राष्ट्रों को संलग्न करने के लिए अन्य मंच बनाए हैं, जहां रूस जैसे नायक नहीं हैं। चीन प्लस मध्य एशिया (सी+सी5) या मध्य एशिया-चीन (5+1) प्रारूप तेजी से उभर रहा है। छह देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 16 जुलाई, 2020 को हुई थी। चीन ने महामारी से लड़ने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को वापस लाने के लिए सहयोग पर जोर दिया। यह बैठक राजनीतिक संबंधों के लिए मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ चीन के मुख्य रूप से आर्थिक संबंधों में बदलाव का प्रतीक है। मध्य एशिया-चीन बैठकें इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति और प्रभाव को सुदृढ़ करेंगी[32]। 25 जनवरी 2022 को, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पांच मध्य एशियाई राष्ट्रों के राष्ट्रपतियों के साथ 'चीन प्लस मध्य एशिया' की एक आभासी शिखर बैठक आयोजित की, ताकि उनके बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा सके। दोनों पक्षों का इरादा *2030 तक चीन-मध्य एशिया व्यापार को 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का है*[33]।

यह ध्यान रखना उचित है कि सी+सी5 सुरक्षा और व्यापार के मामलों में शंघाई सहयोग संगठन के साथ सहयोग कर रहा है। तीसरी सी+सी 5 विदेश मंत्रियों की बैठक जून 2022 में नूरसुल्तान, कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी, जहां सहयोग के दस मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई थी। रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप, चीन और यूरोपीय संघ के बीच आपूर्ति मार्गों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए, चीन मध्य एशिया के माध्यम से विकल्पों पर काम कर रहा है, जिसमें रूस इस रणनीति में सह-भागीदार के रूप में है[34]। यह कभी-कभी "मध्य एशिया में रूस और चीन की शांत प्रतियोगिता" के रूप में जाना जाता है[35]।

एससीओ विस्तार

2010 में एससीओ के ताशकंद शिखर सम्मेलन में नई सदस्यता पर लगी रोक हटा दी गई थी, जिससे समूह के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। संगठन को विस्तारित करने का निर्णय 2014 में दुशान्बे में एससीओ द्वारा लिया गया था। उफा में 2015 में रूस की अध्यक्षता में एससीओ ने भारत और पाकिस्तान

को शामिल करने का निर्णय लिया था। उफा शिखर सम्मेलन कई कारणों से महत्वपूर्ण था, इस तथ्य के अलावा कि यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया था। पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण विकास हुए थे। 2013 में चीन ने पुराने सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने और एशिया को पार करने वाली मल्टीमॉडल परिवहन पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से यूरोप के साथ फिर से जुड़ने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी ओबीओआर बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया। 2014 में, रूस ने क्रीमिया को एनेक्स/फिर से एकीकृत करने के लिए सैन्य कार्रवाई की और पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना किया, जिसने इसे चीन के करीब लाया। दोनों शिखर सम्मेलन पुतिन का अमेरिका-पश्चिम को यह बताने का तरीका था कि रूस अलग-थलग नहीं है और उसके दोस्त और सहयोगी मॉस्को के साथ व्यापार करने के इच्छुक हैं।[36]। रूसी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स और एससीओ शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के बीच बहु-आयामी सहयोग विकसित करने में कदम हैं। शिखर सम्मेलन ने 2025 तक एससीओ की विकास रणनीति और एससीओ उफा घोषणा को अपनाया और संगठन का विस्तार करने और भारत और पाकिस्तान को सदस्यता देने का निर्णय लिया[37]।

> 2010 के ताशकंद शिखर सम्मेलन के बाद, भारत में एससीओ सदस्यता के गुण-दोषों के बारे में एक जीवंत बहस हुई थी। पूर्ण सदस्यता का सबसे बड़ा लाभ, यह तर्क दिया गया था, "यूरेशियन क्षेत्र के मामलों में अधिक दृश्यता" होगी। इसके अलावा, भारत को चीन और पाकिस्तान को रचनात्मक रूप से संलग्न करने के लिए एक मंच मिलेगा। यह भी महसूस किया गया कि एससीओ की सदस्यता भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए लाभप्रद होगी।

एससीओ में भारत के उद्देश्य

भारत 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में समूह में पर्यवेक्षक बना था। 2010 के ताशकंद शिखर सम्मेलन के बाद, भारत में एससीओ सदस्यता के गुण-दोषों के बारे में एक जीवंत बहस हुई थी। पूर्ण सदस्यता का सबसे बड़ा लाभ, यह तर्क दिया गया था, "यूरेशियन क्षेत्र के मामलों में अधिक दृश्यता" होगी। इसके अलावा, भारत को चीन और पाकिस्तान को रचनात्मक रूप से संलग्न करने के लिए एक मंच मिलेगा। यह भी महसूस किया गया कि एससीओ की सदस्यता भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए लाभप्रद होगी। हालांकि, इस बात की आशंका थी कि चीन और रूस के प्रभुत्व वाले समूह में भारत को उसका हक नहीं मिलेगा। चीन-पाकिस्तान की मिलीभगत, विशेष रूप से मध्य एशिया में, एक वास्तविक संभावना भी थी। इसलिए भारत को "पूर्ण सदस्यता की मांग करने वाले मुद्दे पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने" की सलाह दी गई थी[38]।

भारत के लिए समूह में रुचि लेने के कई कारण हैं जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता में भूमिका निभाने के

लिए था। राजदूत राजीव भाटिया का कहना है कि "इतिहास, भू-राजनीति, सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आर्थिक अनिवार्यताओं" के अलावा, एससीओ में शामिल होने के लिए भारत के तीन स्पष्ट उद्देश्य हैं "रूस के साथ संबंधों को घनिष्ठ करना; चीन और पाकिस्तान के प्रभाव की निगरानी और मुकाबला; और सीएआर के साथ सहयोग का विस्तार करें"[39]। उनका मानना है कि मध्य एशिया के साथ भूमि संपर्क की कमी भारत के लिए बड़ी बाधा रही है, विशेषकर चीनी बेल्ट एंड रोड परियोजना और "मोटी चेक बुक" के मद्देनजर। वह इस चुनौती को दूर करने और क्षेत्र के बाजारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नवीन और रचनात्मक पहल की सिफारिश करते हैं[40]।

> 2016 के एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन विभिन्न तरीकों के बारे में बात की, जिनमें भारत को एससीओ सदस्यता से लाभ होने की आशा थी। उन्होंने जोर देकर कहा, "एससीओ के भीतर, भारत मजबूत व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बनाने में एक उत्पादक भागीदार होगा।

ताशकंद में 2016 के एससीओ शिखर सम्मेलन में एससीओ में भारत के प्रवेश की प्रक्रिया दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में एससीओ के प्रति भारत के दृष्टिकोण को "काफी लचीला बहुपक्षवाद" बताया, जहां देश "कई प्रक्रियाओं में शामिल होने" के लिए तैयार है। भारत के लिए, एससीओ व्यापार, परिवहन, संस्कृति और आतंकवाद, कनेक्टिविटी आदि में विस्तारित पड़ोस के देशों के साथ जुड़ने का एक और मंच होगा। एससीओ में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए विशाल क्षमता है और एससीओ ऊर्जा क्लब इस संबंध में वादा करता है। "हम वास्तव में इसे शुद्ध लाभ के रूप में देखते हैं, जो हमारे पास पहले से ही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस नजरिए से हम इसे एक ऐसे समूह के रूप में देखते हैं जिसका मूल्य है और हम भारत में मूल्य को उसके भीतर देखते हैं[41]। 2016 के एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन विभिन्न तरीकों के बारे में बात की जिनमें भारत को एससीओ सदस्यता से लाभ होने की आशा थी। उन्होंने जोर देकर कहा, "एससीओ के भीतर, भारत सुदृढ़ व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बनाने में एक उत्पादक भागीदार होगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, चाबहार समझौते और अश्गाबात समझौते में शामिल होने के भारत के निर्णय का उल्लेख उसकी इच्छा और इरादे के सबूत के रूप में किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के देशों के बीच संपर्क हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने "वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों के निर्बाध प्रवाह" और "दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ सुदृढ़ रेल, सड़क और हवाई संपर्कों का पोषण करने" की आवश्यकता के बारे में बात की। भारत को यह भी आशा है कि उसकी सदस्यता "कट्टरपंथी विचारधाराओं, घृणा, हिंसा और आतंक के खतरों" से निपटने में मदद करेगी[42]।

> ऊर्जा सुरक्षा आदर्श रूप से एससीओ का शीर्ष एजेंडा होना चाहिए क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता इस क्षेत्रीय समूह का हिस्सा हैं।

भारत औपचारिक रूप से 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में एससीओ में शामिल हुआ था। अपने भाषण में, भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत और एससीओ के बीच संभावित सहयोग के क्षेत्रों के रूप में आतंकवाद, शांति और स्थिरता, पर्यावरण परिवर्तन और "भविष्य की ऊर्जा" के खिलाफ लड़ाई के साथ-साथ "ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, खनिज, क्षमता निर्माण, विकास साझेदारी, व्यापार और निवेश" पर जोर दिया[43]।

ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा सुरक्षा आदर्श रूप से एससीओ का शीर्ष एजेंडा होना चाहिए क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता इस क्षेत्रीय समूह का हिस्सा हैं। एक अनुमान के अनुसार एससीओ सदस्य देशों के क्षेत्र में वैश्विक तेल भंडार का लगभग 25%, गैस भंडार का 50% से अधिक, कोयला का 35% और दुनिया के ज्ञात यूरेनियम भंडार का लगभग आधा हिस्सा है[44]। जब ऊर्जा खपत की बात आती है तो चीन सबसे ऊपर है जबकि भारत तीसरे स्थान पर है (बीच में अमेरिका के साथ)[45]।

रूस, दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में से एक, एससीओ एनर्जी क्लब का मुख्य आरंभकर्ता है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के सुचारू निर्यात के लिए सुरक्षित आपूर्ति लाइनें बनाना है। एससीओ ऊर्जा क्लब की स्थापना के लिए ज्ञापन पर मास्को में रूस, अफगानिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, भारत, ताजिकिस्तान, तुर्की और श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए। यह ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सदस्य देशों के उच्च स्तरीय राष्ट्र अधिकारियों, व्यापारिक लोगों और वैज्ञानिकों को एक साथ लाने का इरादा रखता है। यह ऊर्जा उत्पादकों, उपभोक्ताओं और पारगमन देशों को समस्याओं और आम चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। व्यक्तिगत सदस्यों को विशिष्ट चिंताओं और द्विपक्षीय समस्याओं को उठाने के लिए एक मंच मिलेगा[46]।

एससीओ एनर्जी क्लब की पहली बैठक 2017 में एससीओ संवाद सहयोगी तुर्की की अध्यक्षता में हुई थी। मंगोलिया, बेलारूस, ईरान, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे गैर-सदस्य देश, जिन्होंने बैठक में भाग लिया, चीन, जापान, यूरोप, कोरिया और भारत जैसे बाजारों में ऊर्जा के परिवहन में महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं[47]।

> आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार, और धार्मिक अतिवाद एससीओ के लिए, भारत के लिए भी प्रमुख चिंताएं रही हैं।

एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बदलाव हुआ है-उत्पादन केंद्र पश्चिम की ओर बढ़ रहे

हैं जबकि पूर्व में खपत का विस्तार हो रहा है। बैठक का क्षेत्र एससीओ के सदस्य देशों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र है। कोयला और तेल से गैस और नवीकरणीय ऊर्जा में एक और बदलाव/परिवर्तन हुआ है। यहां भी एससीओ एनर्जी क्लब की भूमिका है। अध्ययन तीन तरीकों की पहचान करता है जिसमें यह मदद कर सकता है: वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करना, स्थिर ऊर्जा कीमतों पर बातचीत करना और स्वच्छ और सस्ता ऊर्जा स्रोतों को खोजने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करना[48]। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं के अनुरूप है।

गेटवे हाउस के पास भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में कुछ सुझाव हैं। इसमें कहा गया है कि भारत को रूस के सुदूर पूर्व में सखालिन से कम लागत वाली गैस आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, जो रूस के आर्कटिक क्षेत्र में यमल प्रायद्वीप से गैस की तुलना में सस्ता होगा। यह उपयोगी होगा यदि भारत अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना चाहती है। यह भारत को एससीओ अधिकार क्षेत्र के भीतर ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए एससीओ एनर्जी क्लब की अध्यक्षता की मांग करने की भी सलाह देता है[49]।

आतंकवाद: आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार, और धार्मिक अतिवाद एससीओ के लिए, भारत के लिए भी प्रमुख चिंताएं रही हैं। एक पर्यवेक्षक के रूप में, भारतीय विदेश मंत्री ने नियमित रूप से एससीओ की बैठकों में भाग लिया और समूह की गतिविधियों में भाग लिया, उदाहरण के लिए, आतंकवाद विरोधी अंग क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस)। भारत ने एससीओ और आरएटीएस के साथ सुरक्षा संबंधी सहयोग को घनिष्ठ करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जो विशेष रूप से सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। इसने मई 2022 में एससीओ के सभी सदस्य देशों के आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों की एक बैठक की मेजबानी की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया[50]। तत्कालीन एससीओ महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने नई दिल्ली में अपने 2020 के व्याख्यान में बताया कि, वर्ष 2018 के दौरान, एससीओ सदस्य राष्ट्रों ने आतंकवाद के वित्तपोषण के 10 चैनलों की पहचान की और उन्हें दबा दिया, और 10,000 से अधिक संदिग्ध विदेशी आतंकवादियों को एससीओ देशों में प्रवेश करने से रोक दिया गया। सदस्य देशों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास 'शांति मिशन' जारी रखा[51]।

अफगानिस्तान: अपनी स्थापना के बाद से, अफगानिस्तान की स्थिति एससीओ की एक महत्वपूर्ण चिंता रही है। एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की स्थापना 2005 में हुई थी लेकिन इसकी गतिविधि 2009 में निलंबित कर दी गई थी। अफगानिस्तान से सैन्य वापसी की अमेरिका की घोषणा ने एससीओ को एक स्थिर कारक के रूप में आगे बढ़ाया और समूह में शामिल होने के भारत के निर्णय के पीछे एक महत्वपूर्ण विचार था। एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह ने 2017 में कामकाज फिर से शुरू किया और मंत्रिस्तरीय बैठकें शुरू कीं। मॉस्को (अक्तूबर, 2017), बीजिंग (मई 2018) और बिश्केक (अप्रैल 2020) के बाद, इसकी

आखिरी बैठक 14 जुलाई 2021 को दुशांबे में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों ने अमेरिका की वापसी के कारण अफगानिस्तान में अराजक स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की और "अफगानिस्तान में राजनीतिक निपटान प्रक्रिया, अफगान शांति बहाल करने, विकासशील अर्थव्यवस्था, आतंकवाद का मुकाबला करने और अफगानिस्तान में एक समावेशी राजनीतिक संरचना स्थापित करने" के लिए समर्थन व्यक्त किया[52]। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से बेहद चिंतित भारत ने नवंबर 2021 में अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया था जिसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया था। प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया कि अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह न बने और अफगान समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ काबुल में "खुली और वास्तव में समावेशी" सरकार के गठन का आह्वान किया[53]।

> अपनी स्थापना के बाद से, अफगानिस्तान की स्थिति एससीओ की एक महत्वपूर्ण चिंता रही है।

> भारत सितंबर 2022 में समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद एससीओ की अध्यक्षता करेगा और 2023 में इसकी अध्यक्षता में अगले शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह भारत के लिए समूह को एक नई दिशा देने का अवसर होगा। कनेक्टिविटी, ऊर्जा और व्यापार पर नए विचारों और ठोस पहलों को लाते हुए आतंकवाद और अफगानिस्तान की स्थिति जैसी मुख्य चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनौती है।

मूल्यांकन: संभावनाएं और चुनौतियां

एससीओ की शुरुआत 2001 में शंघाई फाइव से हुई थी, जो 1996 में चीन और पूर्व सोवियत गणराष्ट्रों-रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए बनाया गया एक क्षेत्रीय समूह था। उजबेकिस्तान के शामिल होने के साथ यह एससीओ बन गया। अगले चार वर्षों के दौरान अपने गठन के बाद एससीओ एक एजेंडा अपनाने और अपने बुनियादी संस्थानों के निर्माण में व्यस्त था। इसकी मुख्य चिंता "आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद" से निपटना और अवैध नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई थी। अगले दशक के दौरान एससीओ एजेंडा बहुआयामी और व्यापक हो गया, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा (अफगानिस्तान में उभरती स्थिति को देखते हुए), और आर्थिक, वित्तीय, परिवहन और कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्रों में अधिक सहयोग शामिल था।

मंगोलिया 2004 में एससीओ पर्यवेक्षक बना, जबकि भारत, पाकिस्तान और ईरान 2005 में पर्यवेक्षक राष्ट्रों के रूप में एससीओ में शामिल हुए। 2017 में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में पूर्ण सदस्यता (अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया) और छह "संवाद भागीदारों" (आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की) को स्वीकार करने में रुचि रखने वाले चार पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। 2021 में, ईरान के पूर्ण सदस्य के रूप में परिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया था, और मिस्र, कतर के साथ-साथ सऊदी अरब भी वार्ता भागीदार बन गए[54]। यह अपने आप में नए सदस्यों के लिए संगठन की प्रासंगिकता और आकर्षण को सिद्ध करता है।

एससीओ में भारत की सदस्यता ने क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है। इसने भारत को इस क्षेत्र में विकास का निरीक्षण करने और ऊर्जा और कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं में भाग लेने के लिए एक तंत्र प्रदान किया है। मध्य एशियाई देश एससीओ में भारत की भागीदारी का समर्थन करते हैं क्योंकि वे समान चिंताओं और हितों को साझा करते हैं। वे भारत के सॉफ्ट बैलेंसर की भूमिका निभाने में सहज महसूस करते हैं। यह उनकी बहु-वेक्टर विदेश नीतियों के भी अनुरूप है। मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय और एससीओ ढांचे में साझेदारी हमारी ऊर्जा सुरक्षा और यूरेशिया के साथ जुड़ने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकती है।

एससीओ को पश्चिम-विरोधी/नाटो समूह के रूप में चित्रित करना मुख्य रूप से इसके वास्तविक इरादे और उद्देश्य की सराहना करने में असमर्थता के कारण है। यह अमेरिका/पश्चिम में रूस और चीन के भाषा अवरोध या सामान्य अविश्वास के कारण हो सकता है। एससीओ यूरेशियन देशों के वैकल्पिक दृष्टिकोण और हितों को स्पष्ट करने के लिए एक गैर-पश्चिमी मंच है। निस्संदेह, आतंकवाद, अफगानिस्तान, आर्थिक सहयोग के स्तर और गति आदि सहित विभिन्न मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच मतभेद हैं। लेकिन वे इन मतभेदों को पाटने और एक साझा आधार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और मध्य एशियाई देश ज्यादातर मुद्दों पर काफी हद तक एक ही धरातल पर हैं और एससीओ में एक स्थिर कारक हैं। अपनी 'मल्टी-वेक्टर' विदेश नीति के साथ मध्य एशियाई राष्ट्र रूस, चीन और भारत सहित सभी देशों के साथ रचनात्मक जुड़ाव चाहते हैं[55]।

जब वास्तविक उपलब्धियों और सीमाओं की बात आती है, तो स्टीफन ब्लैंक एससीओ के बारे में बहुत अधिक आशावाद के खिलाफ चेतावनी देते हैं, विशेषकर भारत के लिए। वह हमें याद दिलाते हैं कि रूस और चीन ने वास्तव में कई मुद्दों पर मिलकर काम नहीं किया है। जबकि रूस एससीओ को एक व्यापार ब्लॉक में बदलने के चीनी प्रयासों का समर्थन नहीं करता है, चीन अपनी ओर से कुछ रूसी प्रस्तावों के बारे में उत्साहित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-पाकिस्तान विवाद को एससीओ के ढांचे में लाया जा

सकता है। उन्हें अफगानिस्तान और इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने की पाकिस्तान की इच्छा पर संदेह है, क्योंकि यह अफगानिस्तान में समस्याओं का स्रोत है और भारत के खिलाफ इस्लामी आतंकवाद का समर्थन करता है। ब्लैंक यह भी बताते हैं कि रूस पाकिस्तान को हथियार बेचना जारी रखता है और कई बार आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के लिए उसकी निंदा करने से इनकार कर देता है। इस प्रकार उनका मानना है कि प्रमुख सदस्यों के बीच मतभेद एससीओ की प्रभावशीलता को "एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में" बाधित कर सकते हैं और "इसकी क्षमताओं के विस्तार पर ब्रेक के रूप में काम कर सकते हैं[56]। हालांकि, कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं कि पाकिस्तान एससीओ को पटरी से उतार सकता है। वे सतर्क आशावाद व्यक्त करते हैं और मानते हैं कि "भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ में शामिल होने से संगठन सुदृढ़ होगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान एससीओ जनादेश के अनुसार द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठा सकता है और "एससीओ मंच के विभिन्न तंत्रों द्वारा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने से सदस्यों के बीच विश्वास की कमी को कम करने में मदद मिल सकती है[57]।

एससीओ यूरेशियन देशों के वैकल्पिक दृष्टिकोण और हितों को स्पष्ट करने के लिए एक गैर-पश्चिमी मंच है।

संगठन के आर्थिक महत्व और क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, एससीओ महासचिव ने प्राकृतिक संसाधनों, उत्पादन क्षमताओं, तकनीकी दक्षताओं, निवेश और वित्तीय क्षमता और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरकता की प्रचुरता का उल्लेख किया है। उन्होंने याद दिलाया कि एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है और 18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 20% हिस्सा है (क्रय शक्ति समानता के मामले में, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30%)[58]। हालांकि, अर्थव्यवस्था, वित्त, निवेश, परिवहन, ऊर्जा और कृषि में सहयोग की आवश्यकता के बारे में लगातार शिखर सम्मेलनों में बार-बार घोषणाओं के बावजूद, वास्तविकता यह है कि एससीओ सदस्यों को अभी तक इन मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचना और कार्य योजना को अपनाना बाकी है। एससीओ में यूरेशिया में "स्थिरता के लिए आधार" बनने की क्षमता है यदि सदस्य देश सावधानी से नेविगेट करते हैं। यह व्यापक आर्थिक सहयोग को लागू करके एक "आर्थिक चमत्कार" भी हो सकता है[59]।

ईरान और अब बेलारूस के एससीओ में शामिल होने की संभावना के साथ, इसका पश्चिम विरोधी झुकाव और बयानबाजी तीखी हो सकती है[60]। आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद, उजबेकिस्तान में है, जिसमें उनकी सदस्यता के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

एससीओ अध्यक्ष के रूप में भारत: भावी राह

भारत सितंबर 2022 में समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद एससीओ की अध्यक्षता करेगा और 2023 में इसकी अध्यक्षता में अगले शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह भारत के लिए समूह को एक नई दिशा देने का अवसर होगा। कनेक्टिविटी, ऊर्जा और व्यापार पर नए विचारों और ठोस पहलों को लाते हुए आतंकवाद और अफगानिस्तान की स्थिति जैसी मुख्य चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनौती है। भारत में एससीओ व्यापार परिषद के राष्ट्रीय चैप्टर के अध्यक्ष शिव खेमका ने एससीओ व्यापार परिषद के तंत्र के माध्यम से अंतर-एससीओ सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए पांच-आयामी दृष्टिकोण की सिफारिश की। उन्होंने नवाचार समूहों, प्रौद्योगिकी पार्कों और उच्च तकनीक कंपनियों, ज्ञान-गहन समाधानों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों, अभिनव क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास और वित्तपोषण के सहयोग से एमएसएमई और स्टार्ट-अप के विशेष प्रोत्साहन का भी प्रस्ताव दिया है[61]।

एससीओ में भारत की सदस्यता ने क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। इसने भारत को इस क्षेत्र में विकास का निरीक्षण करने और ऊर्जा और कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं में भाग लेने के लिए एक तंत्र प्रदान किया है। मध्य एशियाई देश एससीओ में भारत की भागीदारी का समर्थन करते हैं क्योंकि वे समान चिंताओं और हितों को साझा करते हैं। वे भारत के सॉफ्ट बैलेंसर की भूमिका निभाने में सहज महसूस करते हैं। यह उनकी बहु- संचालन विदेश नीतियों के अनुरूप भी है[62]। मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय और एससीओ ढांचे में साझेदारी हमारी ऊर्जा सुरक्षा और यूरेशिया के साथ जुड़ने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर भी भारत और मध्य एशियाई देश एससीओ ढांचे के तहत एक साथ आ सकते हैं। भारत कौशल विकास, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास में ठोस भूमिका निभा सकता है।

पाद-टिप्पणियाँ

[1]अशोक मुखर्जी, "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का लाभ उठाना"। मोदी 2.0 में: भारत को सुरक्षित करने का संकल्प। रंजीत पचनंदा और अन्य द्वारा संपादित। नई दिल्ली, पेंटागन, 2021. पृष्ठ 87.

[2]See http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=100

[3]See http://eng.sectsco.org/documents/2002

[4]See http://eng.sectsco.org/documents/2003

[5]See http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=98

[6]हार्टलैंड के उभरते मास्टर के रूप में एससीओ, विटाली वोरोबिएव देखें. http://eng.globalaffairs.ru/number/The-SCO-as-a-Rising -Master-of- the-Heartland-15503

[7]जिल्दिज निछारापोवा, (बिश्केक), अफगान संकट और शंघाई सहयोग संगठन की स्थिरीकरण की नीतियों द्वारा उद्धृत।

[8]एससीओ देशों के सुरक्षा सचिवों की दसवीं बैठक के दौरान रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव का भाषण देखें, मॉस्को अप्रैल 2015.

[9]देखें एम अशरफ हैदरी, कैसे चीन और भारत अफगानिस्तान में शांति सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। रायसीना डिबेट्स, ओआरएफ 18 अगस्त 2018।

10 रेजाउल एच. लस्कर, भारत ने एससीओ समूह की बैठक में अफगानिस्तान के 3 सूत्री रोड मैप का सुझाव दिया। हिंदुस्तान टाइम्स 15 जुलाई 2021।

[10]दीपांजन रॉय चौधरी, भारत ने अश्गाबात समझौते को स्वीकार किया क्योंकि दिल्ली यूरेशियन कनेक्टिविटी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स 1 फरवरी 2018.

[11]यूएसएआईडी पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान पारगमन व्यापार समझौते (एपीटीटीए) का विश्लेषण। मई 2014. पृष्ठ 3.

[12]पूर्वोक्त

[13]सुहासिनी हैदर, "पाकिस्तान को व्यापार के लिए वाघा खोलना चाहिए: गनी". द हिंदू 30 अप्रैल 2015.

[14]पूर्वोक्त

[15]पूर्वोक्त

[16]यूएसएआईडी पाकिस्तान, ओ. पृष्ठ 2.

[17]द हिंदू देखें, 4 जून 2011.

[18]इकोनॉमिक टाइम्स 2 अप्रैल 2022

[19]टी एन निनान, "1991 के 30 वर्ष बाद: हमने एक अर्थव्यवस्था के रूप में क्या हासिल किया, और क्या संभव था". https://www.business-standard.com/ article/opinion/30-years-after-1991-what-we-achieved-as-an-economy-and-what-was-possible-121061801121_1.html

[20]जोनाथन फेनबी "1990 के दशक में चीन में हुई घटनाओं ने उस दुनिया को कैसे आकार दिया जिसमें हम अब रहते हैं", द गार्डियन, 23 अप्रैल 2017. https://www. theguardian.com/world/2017/apr/23/how-events-in-china-in-the-1990s-shaped-the-world-we-live-in-now

[21]पीटर होपकिर्क द ग्रेट गेम: मध्य एशिया में एक साम्राज्य के लिए संघर्ष कोदांशा इंटरनेशनल 1992Lutz Kleveman, The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia http://www.qurtuba.edu.pk/thedialogue/The%20Dialogue/12_3/ Dialogue_July_September2017_229-246.pdf

[22]Lutz Kleveman, The New Great Game: Blood and Oil in Central Asiahttp://www.qurtuba.edu.pk/thedialogue/The%20Dialogue/12_3/ Dialogue_July_September2017_229-246.pdf
लुत्ज़ क्लेवेमैन, द न्यू ग्रेट गेम: मध्य एशिया में रक्त और तेल http://www.qurtuba.edu.pk/thedialogue/The%20Dialogue/12_3/ Dialogue_July_September2017_229-246.pdf

[23]जीन-पियरे लेहमैन, "मध्य एशिया: 21वीं सदी के नए वैश्विक विकार में महान खेल". https://www.imd.org/research-knowledge/articles/central-asia-the-great-game-in-the-new-global-disorder-of-the-21st-century/

[24]एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन (आईजीओ) सदस्य देशों के बीच अंतर-सरकारी समझौते द्वारा स्थापित किया गया है। आईजीओ को कम से कम तीन सदस्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन बड़े वैश्विक निकाय हो सकते

हैं, उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र (185 सदस्यों के साथ)। वे एक क्षेत्र (जैसे, अमेरिकी राष्ट्रों का संगठन) तक सीमित हो सकते हैं या सभी क्षेत्रों (जैसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के सदस्य हो सकते हैं। वे एकल-उद्देश्य (जैसे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) हो सकते हैं, या कई उद्देश्य हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)।https://www.britannica.com/topic/international-organization

[25]क्विंगुओ जिया "शंघाई पांच की सफलता: रुचियां, मानदंड और व्यावहारिकता"" http://www.comw.org/cmp/fulltext/0110jia.htm

[26]एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन (आईजीओ) सदस्य देशों के बीच अंतर-सरकारी समझौते द्वारा स्थापित किया गया है। आईजीओ को कम से कम तीन सदस्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन बड़े वैश्विक निकाय हो सकते हैं, उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र (185 सदस्यों के साथ)। वे एक क्षेत्र (जैसे, अमेरिकी राष्ट्रों का संगठन) तक सीमित हो सकते हैं या सभी क्षेत्रों (जैसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के सदस्य हो सकते हैं। वे एकल-उद्देश्य (जैसे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) हो सकते हैं, या कई उद्देश्य हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)।https://www.britannica.com/topic/international-organization

[27]मोहम्मद नजमुल इस्लाम, "ब्रिक्स, मिक्टा, एससीओ और आईबीएसए: उभरते वैश्विक संगठन और समूह- नई विश्व व्यवस्था के लिए एक प्रतिमान बदलाव", अंकारा यिल्दिरिम बेयाज़ित विश्वविद्यालय, जनवरी 2020।
https://www.researchgate.net/publication/338659670_BRICS_MIKTA_SCO_and_
IBSA_EMERGING_GLOBAL_ORGANIZATIONS_AND_GROUPS_-A_Paradigm_Shift_for_New_World_Order

[28]संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों का विभाग https://dppa.un.org/en/shanghai-cooperation-organization

[29]एससीओ सचिवालय ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के साथ साझेदारी भी स्थापित की। यह ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी), एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) और आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओसीटी) के साथ भी सहयोग करता है। राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों का विभाग (डीपीपीए), और यूएनआरसीसीए (मध्य एशिया के लिए निवारक कूटनीति के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्र) आतंकवाद और हिंसक अतिवाद की रोकथाम जैसे मामलों पर एससीओ के साथ सहयोग करते हैं।

[30]एससीओ मुक्त व्यापार क्षेत्र परियोजना: समस्याएं और संभावनाएं यूरेशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, साप्ताहिक बुलेटिन, 28.02.2017 - 06.03.2017, No 105. https://eurasian-research.org/wp-content/uploads/2020/06/Weekly-e-bulletin-28-02-2017-06-03-2017-No-105.pdf

[31]फोज़िल मशराब, "शंघाई सहयोग संगठन ठहराव की अवधि में प्रवेश करता है". द टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया, 03 अक्तूबर 2020 (मूल रूप से जेम्सटाउन फाउंडेशन के यूरेशिया डेली मॉनिटर द्वारा प्रकाशित)) https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/22987- shanghai-cooperation-organization-enters-period-of-stagnation

[32]उमीदा हाशिमोवा, चीन ने मध्य एशिया के साथ 5+1 प्रारूप बैठकें शुरू कीं, द डिप्लोमैट, 20 जुलाई, 2020 https://thediplomat.com/2020/07/china-launches-51-format-meetings-with-central-asia/

[33]क्रिस डेवोनशायर-एलिस, 'चाइना प्लस सेंट्रल एशिया' बैठक यूरेशियन सुरक्षा और व्यापार को एक साथ खींचती है, सिल्क रोड ब्रीफिंग, 26 जनवरी, 2022 https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/01/26/china-plus-central-asia-meeting-draws-eurasian-security-and-trade- closer-together/

[34]क्रिस डेवोनशायर-एलिस "चीन ने मध्य एशियाई देशों के साथ दस सहयोग बिंदु रखे", https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/06/12/china-lays-out-ten-cooperation-points-with-central-asian-nations/

[35]"मध्य एशिया में रूस और चीन का शांत मुकाबला" https://www.gisreportsonline.com/russias-and-chinas-quiet-contest-in-central-asia,politics,2525,report.html

[36]यह रूस-जॉर्जिया युद्ध के मद्देनजर येकातेरिनबर्ग में 2009 में ब्रिक और एससीओ के जुड़वां शिखर सम्मेलनों की याद दिलाता है।

[37]ब्रिक्स और एससीओ शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण निर्णयों से भरे हुए हैं-पुतिन तास, 10 जुलाई 2015, 19:41 https://tass.com/russia/807771

[38]मीना सिंह रॉय, "एससीओ के विस्तार की गतिशीलता" https://www.idsa.in/idsacomments/DynamicsofExpandingtheSCO_msroy_040411

[39]मध्य एशिया कई कारणों से भारत के लिए महत्वपूर्ण है: ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंध, क्षेत्र में महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर, वर्तमान भू-राजनीति, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा। अधिक जानकारी के लिए पी. एल. डैश एड में "भारत और मध्य एशिया का महत्व" देखें। भारत और मध्य एशिया: संक्रमण के दो दशक, (नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)): 01-11.

[40]राजीव भाटिया, "भारत एससीओ से कैसे लाभ उठा सकता है", हिंदुस्तान टाइम्स, 25 नवंबर 2020. https://www.hindustantimes.com/analysis/how-india-can-benefit-from-sco/story-lvHNVzB99Asw6EPcgfE6NK.html

[41]एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए ताशकंद में प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा पर सचिव (पश्चिम) द्वारा मीडिया ब्रीफिंग का प्रतिलेख, 22 जून, 2016, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, https://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/26952/ Transcript_of_Media_Briefing_by_Secretary_West_on_PMs_forthcoming_visit_to_Tashkent_for_SCO_Summit_June_22_2016

[42]एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए ताशकंद में प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा पर सचिव (पश्चिम) द्वारा मीडिया ब्रीफिंग का प्रतिलेख, 22 जून, 2016, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार https://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26948/Speech_by_Prime_Minister_at_SCO_Summit_June_24_2016

[43]अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन, 09 जून, 2017, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस वक्तव्य के तैयार पाठ का अंग्रेजी प्रतिपादन https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/28518/English_rendition_of_Prepared_text_of_Press_Statement_by_Prime_Minister_at_SCO_Summit_in_Astana_June_09_2017

[44]SCO एनर्जी क्लब: संरचना अंतरराष्ट्रीय बातचीत के लिए तैयार है, न कि शंघाई सिक्स के कुलीन क्लब, 26. 03. 2015 http://infoshos.ru/en/?idn=13913

[45]देश द्वारा ऊर्जा की खपत 2022https://worldpopulationreview.com/country-rankings/energy-consumption-by-country

[46]"शंघाई सहयोग संगठन ने ऊर्जा क्लब की स्थापना की "ऊर्जा खुफिया", , 5 दिसंबर
, 2013 https://www.energyintel.com/0000017b- a7c7-de4c-a17b-e7c78ef70001

[47]चैतन्य गिरि और आशना अग्रवाल, "भारत और प्रभावशाली एससीओ एनर्जी क्लब" गेटवे हाउस, 2 अप्रैल 2019, https://www.gatewayhouse.in/india-sco-energy/

[48]गोंग झे, विश्लेषण: एससीओ शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सहयोग के लिए उज्ज्वल संभावनाएं" https://news.cgtn.com/news/3d3d414d3245444d78457a6333566d54/share_p.html

[49]चैतन्य गिरि और आशना अग्रवाल, "भारत और प्रभावशाली एससीओ एनर्जी क्लब" गेटवे हाउस, 2 अप्रैल 2019, https://www.gatewayhouse.in/india-sco-energy/

[50]"भारत ने SCO-RAT बैठक की मेजबानी की; अफगानिस्तान में स्थिति पर ध्यान केंद्रित", इकोनॉमिक टाइम्स, पीटीआई, अंतिम अद्यतन: 16 मई, 2022, 12:37 PM IST, https:// economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-hosts-sco-rats-meet-focus-on-situation-in-afghanistan/articleshow/91591122. cms

[51]"शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के भविष्य के प्रक्षेपवक्र और भारत की भूमिका पर व्याख्यान राजदूत व्लादिमीर नोरोव, महासचिव, एससीओ, भारतीय विश्व मामलों की परिषद, नई दिल्ली, 13 जनवरी 2020. https://www.icwa.in/show_content. php?lang=1&level=1&ls_id=4610&lid=3483

[52]ताजिकिस्तान की राजधानी ने SCO-अफगानिस्तान संपर्क समूह की बैठक की मेजबानी की
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/politics/20210715/tajik-capital-hosts-sco-afghanistan-contact-group-meeting

[53]चैतन्य गिरि और आशना अग्रवाल, "भारत और प्रभावशाली एससीओ एनर्जी क्लब" गेटवे हाउस, 2 अप्रैल 2019, https://www.gatewayhouse.in/india-sco-energy/

[54]"भारत ने SCO-RAT बैठक की मेजबानी की; अफगानिस्तान की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें", इकोनॉमिक टाइम्स, पीटीआई, अंतिम अद्यतन: 16 मई, 2022, 12:37 IST,https:// economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-hosts-sco-rats-meet-focus-on-situation-in-afghanistan/articleshow/91591122. cms

[55]13 जनवरी 2020 को भारतीय विश्व मामलों की परिषद, नई दिल्ली के एससीओ के महासचिव, राजदूत व्लादिमीर नोरोव द्वारा "शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के भविष्य के प्रक्षेपवक्र और भारत की भूमिका पर व्याख्यान"। https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=4610&lid=3483

[56]ताजिकिस्तान की राजधानी ने एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की बैठक की मेजबानी की
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/politics/20210715/tajik-capital-hosts-sco-afghanistan-contact-group-meeting

[57]भारत ने SCO-RAT बैठक की मेजबानी की; अफगानिस्तान की स्थिति पर ध्यान केंद्रित बिजनेस स्टैंडर्ड, अंतिम बार 17 मई, 2022 को अपडेट किया गया 01:45 IST https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-hosts-sco-rats-meet-focus-on-the-situation-in-afghanistan-122051600514_1.html

[58]शंघाई सहयोग संगठन https://dppa.un.org/en/shanghai-cooperation-organization, Downloaded on 29 June 2022

[59]"एससीओ 2019 शिखर सम्मेलन: भारत से एक दृश्य", डॉ संजीव कुमार और डॉ अतहर जफर, भारतीय विश्व मामलों की परिषद, नई दिल्ली, 11 जुलाई 2019. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=2804&lid=2162

[60]स्टीफन ब्लैंक, "क्या उफा में एससीओ शिखर सम्मेलन एक सफलता थी?", मध्य एशिया-काकेशस विश्लेषक,19/08/2015 https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13261-was-the-sco-summit-in-ufa-a-breakthrough?.html

[61]"भारत, पाकिस्तान ने आधी दुनिया तक एससीओ की पहुंच का विस्तार किया", यूरेशियानेट, जून 8, 2017https://eurasianet.org/india-pakistan-extend-reach-of-sco-to-half-the-world

[62]बीजिंग ने SCO महासचिव के साथ ब्रीफिंग की मेजबानी की, 2019/10/23 http://eng.sectsco.org/news/20191023/590687.html

लेखकों के बारे में

राजदूत डी. बी. वेंकटेश वर्मा

राजदूत डी. बी. वेंकटेश वर्मा 1988 से 2021 तक भारतीय विदेश सेवा के सदस्य थे। अपने राजनयिक करियर के दौरान, उन्होंने विदेश मंत्रालय में, विदेश मंत्री के कार्यालय में और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया। उन्होंने अक्तूबर 2021 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन, स्पेन साम्राज्य और रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत की सुरक्षा और रक्षा नीतियों में व्यापक अनुभव है, जिसमें परमाणु, मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने 2010-2013 के बीच विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रभारी संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया।

वह नागरिक परमाणु पहल की वार्ता में उनके योगदान के लिए 2011 में भारतीय विदेश सेवा में उत्कृष्टता के लिए एस. के. सिंह पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय संबंध (निरस्त्रीकरण अध्ययन) में एम.फिल किया है। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय थिंक-टैंक में वार्ता की है।

प्रोफेसर के. वारिकू

1951 में श्रीनगर (कश्मीर) में जन्मे और एस.पी. कॉलेज और कश्मीर विश्वविद्यालय में शिक्षित, प्रोफेसर कुलभूषण वारिकू ने सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएचडी की। वारिकू ने जेएनयू में 30 से अधिक वर्षों तक पढ़ाया और इसके मध्य एशियाई अध्ययन कार्यक्रम, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू की स्थापना की। वह दो वर्ष (अप्रैल 2019-मार्च 2021) के लिए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली में सीनियर फेलो थे। हिमालय, मध्य एशियाई, झिंजियांग, यूरेशियन और सिल्क रूट स्टडीज के लिए अपनी विशिष्ट सेवा के लिए जाने जाने वाले प्रोफेसर वारिकू 22 पुस्तकों के लेखक/संपादक हैं। इनमें *शिनजियांग: चीन का नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर शामिल है; यूरेशिया और भारत: क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य; हिमालय फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया; दक्षिण और मध्य एशिया में धर्म और सुरक्षा;* (सभी रूटलेज टेलर एंड फ्रांसिस, यूके, यूएसए द्वारा प्रकाशित), *अन्य कश्मीर: काराकोरम हिमालय में समाज, संस्कृति और राजनीति; जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत; कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत; अफगानिस्तान: चुनौतियां और अवसर; बामियान: विश्व विरासत के लिए चुनौती; मध्य एशिया और कश्मीर: एंग्लो-रूसी प्रतिद्वंद्विता और मध्य एशिया के संदर्भ में एक अध्ययन: उभरती हुई नई व्यवस्था।*

वारिकू ने शिनजियांग में बड़े पैमाने पर यात्रा की है; उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के मध्य एशियाई गणराष्ट्र; रूसी संघ के खाकासिया, अल्ताई, बुरयातिया और तुवा गणराष्ट्र; अफगानिस्तान और मंगोलिया। वह *हिमालयन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज* के संस्थापक संपादक हैं, जो 1997 से नियमित रूप से और निर्बाध रूप से प्रकाशित होने वाली एक त्रैमासिक पत्रिका है, जो दक्षिण और मध्य एशिया में हिमालय और ट्रांस-हिमालयन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों के अध्ययन के लिए समर्पित है।

उन्होंने 34 पीएच.डी. और 52 एम.फिल. शोध विद्वानों की देखरेख की है, इस प्रकार हिमालयी और मध्य एशियाई अध्ययन के क्षेत्र में युवा पीढ़ी को प्रेरित, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया है।

प्रोफेसर संजय के. पांडे

डॉ. संजय कुमार पांडे सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं। उन्होंने केंद्र के अध्यक्ष और रूस और मध्य एशियाई क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक के रूप में कार्य किया।

वह राजनीति और समाज, साथ ही रूस और मध्य एशियाई राष्ट्रों की विदेश नीति पर पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में विजिटिंग फेलो थे; चार्ल्स वालेस ट्रस्ट विजिटिंग फेलो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय; और कैम्ब्रिज सेंट्रल एशिया फोरम, कैम्ब्रिज में विजिटिंग फेलो। वह दिसंबर 2014 में उजबेकिस्तान में संसदीय (ओली मजलिस) चुनाव के लिए और दिसंबर 2007, 2016 और 2021 में उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे।

उनके कुछ प्रकाशन हैं:

- "रूस और यूक्रेन: भू-राजनीति द्वारा विभाजित इतिहास द्वारा एकीकृत", (सह-लेखक), जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वॉल्यूम 12, अंक 1 और 2, पीपी.19-28, जनवरी-दिसंबर 2020 (2022 में प्रकाशित);
- "उजबेकिस्तान: शांति प्रगति और समृद्धि के 30 वर्ष", बिजनेस सेंट्रल एशिया, सितंबर 2021, भाग 1, पीपी 24-26; पांडे, संजय कुमार, "रूस और यूक्रेन: साझा अतीत, अलग-अलग धारणाएं और भू-राजनीति", द वीक, 24 जनवरी, 2022। https://www.theweek.in/news/world/2022/01/24/russia-and-ukraine- shared-past-differing-perceptions-and-geopolitics.html;
- कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों का कारण क्या था-और इस क्षेत्र के लिए उनका क्या मतलब है" द वीक, 14 जनवरी, 2022, https://www.theweek.in/news/world/2022/01/14/ what-led-to-the-protests-in-kazakhstan-and-what-they-mean-for-the-region.html;
- "रूस-यूक्रेन संघर्ष: अतीत, वर्तमान और भविष्य", इंडिया टुडे, 25 फरवरी, 2022, https://www.indiatoday.in/news-analysis/ story/russia-ukraine-conflict-war-news-update-1917690-2022-02-25
- "सोवियत संघीय व्यवस्था के बाद सोवियत संघवाद की विरासत" अनुराधा चेनॉय और अर्चना उपाध्याय एड। "रूसी क्रांति के सौ वर्ष: परिप्रेक्ष्य में इसकी विरासत, पालग्रेव मैकमिलन;

- "भारत-रूस संबंधों को संदर्भित करना", *अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन*, (सेज प्रकाशन), 53 (3-4): 227-57 (सह-लेखक);
- आर. मल्होत्रा और पी. एल. दास में "भारत और मध्य एशिया का महत्व"। *भारत और मध्य एशिया: संक्रमण के दो दशक*, (2013) नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस;
- "रूसी पहचान पर बहस में एशिया" अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन (2007) 44 (4): 317-37;
- भारत में "कजाकिस्तान की मल्टी-वेक्टर विदेश नीति और भारत"-कजाकिस्तान: रणनीतिक साझेदारी के लिए संभावनाएं" (2011, अल्माटी: कजाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज) पीपी 71-82;
- "रूसी पहचान पर बहस में एशिया" *अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन* (नई दिल्ली: सेज प्रकाशन), .44 (4), अक्तूबर-दिसंबर 2007: 317-37।

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ.एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज एक आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, सेमिनारों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक सरणी आयोजित करती है और प्रकाशनों का आयोजन करती है। इसमें एक सुभंडारित पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह पत्रिका इंडिया क्वार्टरली प्रकाशित करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा दिया जा सके और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी है।

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

2022